



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 331]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 14, 2001/अग्रहायण 23, 1923

No. 331]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 14, 2001/AGRAHAYANA 23, 1923

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2001

प्रारम्भिक निष्कर्ष

विषय :—संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, यूरोपीय संघ और सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 3000 से 4000 तक के आणविक भार के फ्लैक्सीबल स्लैब स्टाक पालीयोल के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

सं. 41/1/2001-डीजीएडी.— भारत सरकार 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए,

क. प्रक्रिया

2. निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया गया है:-

- (i) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके पश्चात् प्राधिकारी भी कहा गया है) को उपरोक्त नियमों के अंतर्गत घरेलू उद्योग की ओर से मै0 मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एम0पी0एल) लिखित याचिका प्राप्त हुई है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, यूरोपीय संघ और सिंगापुर (जिसे इसके बाद संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित 3000 से 4000 तक के आणविक भार का फ्लैक्सीबल स्लैब स्टाक पालीयोल (जिसे इसके बाद संबद्ध वस्तु या एफ0एस0पी0 कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाया गया है।

- (ii) प्राधिकारी ने उक्त नियम के उप-नियम 5(5) के अनुसार जांच की कार्रवाई शुरू करने से पहले याचिकाकर्ता द्वारा किए गए पाटन के आवेदन की प्राप्ति के विषय में भारत में संबंध देशों के दूतावास प्रतिनिधियों को सूचित किया।
- (iii) प्राधिकारी ने 21 सितम्बर, 2001 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया जिसके द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची 1 के अध्याय शीर्ष 39.07 के तहत आने वाले फलैक्सीबल स्लैब स्टॉक पालीथेन के आयातों के संबंध में पाटनरोधी कार्रवाई आरम्भ की गई।
- (iv) प्राधिकारी ने उक्त सार्वजनिक सूचना की प्रति ज्ञात निर्यातकों, आयातकों, उद्योग संघों और शिकायतकर्ता को भेजी और उन्हें अपने विचार लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया।
- (v) प्राधिकारी ने उपरोक्त नियम 6 के उप-नियम (3) के अनुसार याचिका की एक प्रति सभी ज्ञात निर्यातकों और भारत में संबंध देश के दूतावासों को भेजी।
- (vi) प्राधिकारी ने अपेक्षित सूचना प्राप्त करने के लिए संबंध देशों के निम्नलिखित निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी:-
1. मैसर्स शैल ईस्टर्न पेट्रोलियम (प्रा०) लिमि०, सिंगापुर- 239920
 2. मैसर्स वेयर पाल्यूरेशन एशिया (प्रा०) लिमि० सिंगापुर- 189271
 3. मै० सान्यो कैमिकल्स, जापान
 4. मै० वेयर पाल्यूरेशन एशिया (प्रा०) लिमि० जर्मनी
 5. मै० रिपसोल क्योमिका एस०ए० स्पेन
 6. मै० द डो कैमिकल्स कंपनी, टेक्सस - 77541, यू०एस०ए०
 7. मै० द डो कैमिकल्स कंपनी, टेक्सस - 775720- 585 यू०एस०ए०
- (vii) नई दिल्ली में संबंध देशों के दूतावासों/ प्रतिनिधियों को भी जांच शुरू होने के बारे में इस अनुरोध के साथ सूचित किया गया कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावली का उत्तर निर्धारित समय के भीतर देने की सलाह दें।
- (viii) संबंध वस्तु के निम्नलिखित उपयोक्ताओं/आयातकों को प्रश्नावली भेजी गई थी:-
1. मै० आगोश पोलट्रीन फोम प्रा०लि०, चंडीगढ़
 2. मै० अरविन्द इन्टरनेशनल लिमि०, कलकत्ता
 3. मै० बनमोर फोम प्रा० लि० बनमोर, जिला मुरैना म०प्र०
 4. मै० कोजी फोम प्रा०लि० चन्द्रपाड़ा, पालघर थाना
 5. मै० डी०पी० फोम प्रा० लि० पाडीचेरी- 605101
 6. मै० झूरा फोम प्रा०लि०, दादर, नागर, हवेली
 7. मै० डायना फोम प्रा०लि०, उडीसा- 757043
 8. मै० देवी पोल्यूरेशन प्रा० लि०, तनदेदूमूला, तालीघाटपूरी, जि० नासिक
 9. मै० इनके फोम प्रा०लि०, ग्राम खेखरा, तहसील बागपत, जिला मेरठ, उ०प्र०
 10. मै० फिदर फोम इन्टरप्राइजेज प्रा०लि०, नोएडा- 201301
 11. मै० फोम हाउस (इंडिया) प्रा०लि० एम०आई०डी०सी० टेल्को, महाराष्ट्र
 12. मै० फिदर फोम इन्टरप्राइजेज प्रा०लि०, सिलवसा
 13. मै० जॉय फोम प्रा०लि० रानीपेट

14. मै० जूही फोम प्रा०लि०खारर (पंजाब) - 140 031
15. मै० कूरलोन लिमि०, भुवनेश्वर - 751 031
16. मै० कमल फोम, पाडिचेरी - 605 009
17. मै. एम०आर० फोमस प्रा०लि०, हैदराबाद
18. मै० मल्लीविन फोम प्रा०लि० कलकत्ता - 700 016
19. मै० मॉडर्न फोम उद्योग, ग्राम काका, लुधियाना
20. मै० एन०एल० फोम इन्डस्ट्री, अहमदाबाद
21. मै० नटशन फोम मैन्यु० प्रा०लि०, ग्राम नन्ददोली, जिला मेहसाना
22. मै० पैनामा पोल्युस्ट्रिन प्रोडक्ट प्रा० लि०, गाजियाबाद
23. मै० पल्लवी फोम इन्ड० प्रा०लि० नोएडा, दादरी रोड (उ०प्र०) जिला गाजियाबाद
24. मै० पोली० फोम चन्दूपाड़ा, जिला थाने
25. मै० प्रभात पोल्यूरथिन प्रा०लि०, पाडीचेरी
26. मै० प्रताप पोल्यूरथिन, प्रा.लि., कलकत्ता - 700 001
27. मै. पी०यू० फोम प्रा०लि०, कलकत्ता - 700 007
28. मै० राज लेदर क्लोथ इन्ड्री० प्रा०लि०, जिला सोनीपत
29. मै० शीला फोम प्रा०लि०, गाजियाबाद, उ०प्र०- 201 101
30. मै० एस०एस०एफ० इन्ड्री० लिमि०, पटना - 800 004
31. मै० शीला फोम प्रा०लि० कलोल तालूकाकाडी, नोएडा, उ०प्र०
32. मै. तिरुपति फोम लिमि०, जिला मेहसाना
33. मै० तिरुपति फोम लिमि०, तालुक कलोल
34. मै० यू० फार्म प्रा० लि०, हैदराबाद - 500 018
35. मै० सूर्या फोम, पांडीचेरी
36. मै० अर्पना पालीप्रोडक्ट्स लिमि०, जयपुर - 302 001 राजस्थान
37. मै० सॉफ्ट फोम इन्ड्रू० प्रा०लि०, मैडकोल इन्ड्रू० एरिया, आर०आर० जिला 501 401 आन्ध्र प्रदेश
38. मै० मद्रास पोलीमात्तल्डस, माल्यूपूर, चेन्नई- 4
39. मै० जे०जे० फोम प्रा०लि०, जिला गाजियाबाद (उ०प्र०)
40. मै० एम०एच० पोलीमर प्रा०लि०, दादरी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

(ix) कई उपयोक्ताओं/आयातकों ने अधिसूचना जारी किये जाने के प्रति अपना उत्तर प्रस्तुत कर दिया है। निर्यातकों में से मैसर्स शैल ईस्टर्न पेट्रोलियम (प्रा०) लिमि०, सिंगापुर, मैसर्स बेयर पाल्युस्थेन्स एशिया प्राइवेट लिमि० सिंगापुर और मैसर्स डो-कैमिकल्स कम्पनी, संयुक्त राज्य अमेरिका अधिसूचना शुरू किये जाने के प्रति उत्तर प्रस्तुत किया है।

(x) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंशों को प्राधिकारी द्वारा रखी गयी सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध रखा और उसे हितबद्ध पार्टियों द्वारा निरीक्षण हेतु खुला रखा।

- (xi)**** इस अधिसूचना में, हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना प्रदर्शित होती है, जिसे नियमों के तहत प्राधिकारी द्वारा ऐसा ही माना गया है।
- (xii) जांच में 1 अक्टू, 2000 से 30 जून, 2001 तक की अवधि शामिल है।
- (xiii) व्यापक परिचालन के लिए जांच शुरूआत को नोटिस की प्रतियां फिक्की, सी आई आई, एसोचैम इत्यादि को भी भेजी गई थीं।

ख. याचिकाकर्ता के विचार

3. याचिकाकर्ता ने अपने अनुरोधों में निम्नलिखित प्रमुख तर्क उठाए:-

1. चूंकि केवल वे ही संबद्ध वस्तु के एकमात्र उत्पादक हैं, अतः घरेलू उद्योग की ओर उसे आवेदन दायर करने का उनका हक बनता है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता किसी भी संबद्ध उत्पाद के आयात / निर्यात करने वालों से संबंधित नहीं है।
2. भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादन किये जा रहे फ्लैक्सिबल स्लेब स्टाक पालियोल और संबद्ध देशों से निर्यात किये जा रहे फ्लैक्सिबल स्लेब स्टाक पालियोल में कोई ज्ञात अन्तर नहीं है। भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित फ्लैक्सिबल स्लेब स्टाक पालियोल और संबद्ध देशों से आयातित फ्लैक्सिबल स्लेब स्टाक पालियोल, प्रक्रिया और प्रौद्योगिकीय कार्य और उपयोग, उत्पाद की विशेषता, मूल्य निर्धारण, वितरण व विपणन तथा सामान के शुल्क (टैक्स) वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और व्यापारिक तौर पर प्रति स्थापनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों को अदल-बदल करके उपयोग में ला रहे हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित फ्लैक्सिबल स्लेब स्टाक पालियोल को पाटनराधी नियमों के अनुसार इस श्रेणी में आने वाली वस्तुओं के रूप में माना जाना चाहिए।
3. संबद्ध देशों के निर्यातकों ने अपने भारतीय एजेंटों के माध्यम से काफी मात्रा के लिये आदेश दिये हैं। काफी सामग्री पहले ही भारतीय पत्नों पर पहुंच चुकी है और काफी सामग्री पारगमन में होने की सूचना है। घरेलू उद्योग को काफी हानि हो रही है और यदि पाटित मूल्यों पर आयात करने की मौजूदा प्रवृत्ति रहती है तो घरेलू उद्योग को अपनी सुविधाएं बन्द करनी पड़ सकती है।
4. आयातित सामग्री के पहुंच मूल्य, घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्यों से काफी कम होते हैं। इसके अलावा, संबद्ध देशों के निर्यातक यदि मौजूदा मूल्यों पर सामग्री का प्रस्ताव करना जारी रखते हैं तो घरेलू उद्योग को अपने मूल्यों को और कम करने के लिये मजबूर होना पड़ेगा और उन्हें काफी हानि उठानी पड़ेगी। पहले ही घरेलू उद्योग को पाटित आयातों और संबद्ध देशों से

आयात द्वारा किये गये प्रस्ताव के कारण मूल्यों को कम करने के लिये मजबूर होना पड़ रहा है ।

5. संबद्ध देशों में उत्पादकों की संबद्ध वस्तुओं के लिये अच्छी क्षमता होने की सूचना है । इस प्रकार यदि इस चरण में पाटन को नियंत्रित नहीं किया जाता है तो बड़े पैमाने पर आयात किया जाना आवश्यक हो जाता है ।
6. फ्लैक्सिबल स्लैब स्टॉक पालियोल के पाटित आयात से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है और जिन्हें निकट भविष्य में होने वाले संभावित भारत आयात से और अधिक हानि होने का खतरा है ।

ग. आयातकों और उपयोगकर्ताओं के विचार

4. मैसर्स शीला फोम प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स फेडर फोम प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स भारत फोम उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स जेओजेओ फोम प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स एमओएचओ पालिमर्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स वैल्ब्रोस फोम प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स वैल्ब्रोस फोम प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स अरविन्द इन्टरनेशनल लिमिटेड, मैसर्स कनसफ फोम प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स फीलफोर कम्पेंट प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स तिरुपति फोम लिमिटेड, मैसर्स तिरुपति फोम लिमिटेड, मैसर्स एसओएसओएफओ इन्डस्ट्रीज लिमिटेड एवं मैसर्स जॉय फोम प्राइवेट लिमिटेड की ओर से किया गया प्रतिवेदन निम्नप्रकार से है -

क. कि विभिन्न तकनीकी विशेषज्ञों का यह सुविचारित मत है कि किसी पोलीथॉल संयंत्र का स्वीकार्य आकार 80,000 एमओटीपीओए के क्षेत्र में होता है । मानकीकृत प्रौद्योगिकी, स्टीरीन मोनोमर/प्रोपीलीन आक्साइड (एसओएमओपीओओमार्ग) है । केवल इस प्रौद्योगिकी के साथ ही तथा उपर्युक्त क्षमता किसी पोलीथॉल संयंत्र को वाणिज्यिक रूप से स्वीकार्य बना सकती है । क्षमता में कोई कमी अथवा प्रौद्योगिकी में परिवर्तन स्वतः ही उत्पादन की लागत को बहुत अधिक कर देगा । तथापि याचिकाकर्ता के संयंत्र की क्षमता केवल 14000 एमओटीपीओए है और इसमें एसओएमओपीओओमार्ग प्रौद्योगिकी प्रयुक्त नहीं होती है । याचिकाकर्ता की उत्पादन प्रक्रिया और अन्य वस्तुएं प्रौद्योगिकीय रूप में पुरानी हैं और वाणिज्यिकीय रूप में व्याप्य नहीं हैं और इसके परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता द्वारा बनाये जान रहे उत्पादों का मूल्य अवास्तविक रूप से अधिक है ।

ख. याचिकाकर्ता द्वारा प्रयोग में लाई जा रही घटिया प्रौद्योगिकी के कारण फ्लैक्सिबल स्लैब स्टॉक पालियोल की गुणता भौतिकीय दृष्टि से और प्रतिकूल रूप से प्रभावित है और इसके फलस्वरूप इसे कच्ची सामग्री के रूप में फ्लैक्सिबल स्लैब स्टॉक पालियोल को उपयोग में लाने वाले अन्य सह उत्पादों का विनिर्माण और गुणवत्ता प्रभावित होती है ।

ग. सुरक्षा के महानिदेशक ने दिनांक 17-9-1998 के अपने अंतिम निष्कर्षों द्वारा फ्लैक्सिबल स्लैब स्टॉक पालियोल के संबंध में सुरक्षा शुल्क लगाया था । मौजूदा

मामले में घरेलू उद्योग जानबूझ कर माननीय नामित प्राधिकारी की मशीनरी का दुरुपयोग करने का प्रयास कर रहा है ताकि वह अपने लिये अनुचित लाभ और अनावश्यक सुखा ले सके। घरेलू उद्योग इस प्रकार का आवश्यक वाणिज्यिक और प्रचलनात्मक उपाय करने में असफल रहा जो इसे वाणिज्यिक तौर पर स्वीकार्य बनाने के लिये अपेक्षित थे। याचिकाकर्ता को सकारात्मक समायोजन करने के लिये 18 महीनों का समय दिया गया था। घरेलू उद्योग को अपनी खुद की अक्षमताओं के लिये अनुचित लाभ लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, विशेषकर कि कथित क्षति समग्र तौर पर उनकी खुद अक्षमताओं के कारण है और इसका फ्लैक्सीबल स्लैब स्टॉक पालीयॉल के आयात से कोई भी संबंध नहीं है।

घ. याचिकाकर्ता एक बहु उत्पादी कंपनी है। पोलियॉल की विभिन्न श्रेणियों के अलावा और वह प्रोपोलीन आक्सीसाइड, प्रोपोलीन ग्लिकोल, डी०प्रोपीलीन, ट्री प्रोपोलीन ग्लिकोल और डी०सी०पी० और डी०सी०आई०पी० ई का विनिर्माण करती है। इन परिस्थितियों में फ्लैक्सीबल स्लैब स्टॉक पालीयॉल के लिये निर्धारित लागत के आबंटन को सुनिश्चित करना बहुत ही मुश्किल है। याचिकाकर्ता को स्पष्टरूप से फ्लैक्सीबल स्लैब स्टॉक के विनिर्माण के और इस संबंध अनुपातिक रूप से निर्धारित लागत और अन्य प्रभार संविभाजित करने चाहिए। याचिकाकर्ता ऐसा करने में असफल रहा है।

ड. याचिकाकर्ता द्वारा फ्लैक्सीबल स्लैब स्टॉक पालीयॉल का उत्पादन नियमित नहीं है और यह मौसमी है अर्थात् फ्लैक्सीबल स्लैब स्टॉक पालीयॉल का विनिर्माण सारे वर्ष भर नहीं किया जाता है बल्कि इसका विनिर्माण टुकड़ों में किया जाता है। इन परिस्थितियों में याचिकाकर्ता को वर्ष भर निर्धारित लागत घटक का आबंटन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जबकि वस्तु का विनिर्माण केवल एक सीमित अवधि में ही होता है। याचिकाकर्ता ने जान बूझकर उपर्युक्त तथ्यों को उजागर नहीं किया और वह फ्लैक्सीबल स्लैब स्टॉक पालीयॉल के संबंध में उत्पादन की अधिक लागत संवितरित करके अनुचित लाभ लेने की कोशिश कर रहा है। माननीय नामित माननीय प्राधिकारी को याचिकाकर्ता को निदेश देना चाहिए कि वह अपनी लागत आबंटनों के संबंध में सभी आवश्यक और विस्तृत आंकड़े प्रस्तुत करे।

च. याचिकाकर्ता ही भारत में इस उत्पाद का एक मात्र विनिर्माता है। याचिकाकर्ता ने भारत में अपने एकाधिकार को सुदृढ़ करने के लिये और अपने प्रचलनात्मक और वाणिज्यिक अक्षमताओं के बावजूद प्रौद्योगिकीय रूप से बेहतर और वाणिज्यिक रूप स्वीकार्य आयात से किसी भी प्रतियोगिता को टालने के लिये मौजूदा याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता की कुल क्षमता भारत में फ्लैक्सीबल स्लैब स्टॉक पालीयॉल के लिये मांग 35000 एम०टी० पी०ए०के० करीब है और यह वर्तमान में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत- 15 प्रतिशत की दर पर बढ़ रही है।

छ. सभी कैंमिकल्स और प्लास्टिक के मूल्य में समीक्षाधीन अवधि सहित गत वर्ष के दौरान अवास्तविक रूप से काफी अधिक और अस्वीकार्य रहे।

इन आयातकों में से मैसर्स शीला फोम प्रा० लिमिटेड और मैसर्स जॉय फोम प्रा० लिमि० ने आयातक के लिये निर्धारित प्रश्नावली में सूचना प्रस्तुत की। यह सूचना अपूर्ण है क्योंकि इन दोनों फर्मों ने आयातक की प्रश्नावली के अपेक्षित अनुबंध को प्रस्तुत नहीं किये।

5. मैसर्स तिरुपति फोम लिमिटेड का प्रतिवेदन निम्नप्रकार से है -

कि वे एक प्रसिद्ध बहुराष्ट्रीय विनिर्माता से हीटरोपालियोल बस्नील 3010 की एक विशेष कोटि को उपयोग में लाते रहे हैं और वे सीधे ही इस उत्पाद का आयात करते हैं। यह विशेष कोटि के पालियोल का वर्तमान में घरेलू उत्पादक द्वारा विनिर्माण नहीं किया जाता कि उनके पास विनिर्माण की अति आधुनिक सुविधा है, जिसके लिये विशेष तकनीकी अपेक्षाओं की जरूरत होती है और यह अपेक्षाएं वे घरेलू निर्माताओं से प्राप्त करने में असफल हैं। घरेलू उत्पादकों को सीमा शुल्क और विशेष अतिरिक्त शुल्क का संरक्षण प्राप्त है कोई और शुल्क लगाने की बात उनके कारोबार के लिये हानिकारक रहेगी

कंपनी ने आयातकों के लिये निर्धारित प्रश्नावली के तहत कुछ सूचना प्रस्तुत की है लेकिन उन्होंने सभी अपेक्षित अनुबंध प्रस्तुत नहीं किये हैं जैसा कि आयातक प्रश्नावली के तहत अपेक्षित है।

6. मैसर्स डी०पी० फोम प्राइवेट लिमिटेड का प्रतिवेदन निम्नप्रकार से है -

कि पाटनरोधी के प्रति संरक्षण प्राप्त करने वाले घरेलू पालियोल उद्योग को कहा जाना चाहिए कि वे अन्तराष्ट्रीय मानकों के अनुसार गुणवत्ता बनाये और यह लागत प्रभावी भी होना चाहिए। घरेलू उद्योग कोई लागत विश्लेषण नहीं कर रहा है और वे अन्तराष्ट्रीय मूल्यों की तुलना में अपने मूल्य निर्धारित कर रहे हैं। उनके सामान की गुणवत्ता बैच दर बैच भिन्न होती है। घरेलू उद्योग को गुणवत्ता बनाई रखनी चाहिए और अपनी उत्पादन लागत के अनुसार उनकी एक मूल्यनीति होनी चाहिए।

7. मैसर्स यू०- फोम प्राइवेट लिमिटेड का प्रतिवेदन इस प्रकार है -

कि आयात से कम मूल्यों के कारण स्थानीय उद्योगों की स्थिति लाभकारी होने का मुद्दा इस उत्पाद के लिये विशेष रूप से प्रयोजनीय नहीं है। लेकिन व्यावहारिक रूप से सभी सामान का देश में आयात किया जा रहा है। अतः याचिकाकर्ता को संरक्षण देने का विचार ठीक नहीं रहेगा। छोटे पैमाने के वे सभी उद्योग जिनके पास द्रवत्व की कमी है वे याचिकाकर्ता के उत्पादों को संरक्षण देना जारी रखेंगे यद्यपि कि लागत इस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ अधिक हो सकती है कि छोटा उद्यम कंटेनर लाट के लिये निवेश करने की बजाय कम मात्रा स्माल लाट में आर्डर देने की स्थिति में होते हैं। अतः यह स्थानीय उद्योग और याचिकाकर्ता के लिये उचित रहेगा कि वे उचित/पारस्परिक लाभार्थी सहयोग की योजना बनाये।

घ. निर्यातकों के विचार

8. मैसर्स शेल ईस्टर्न पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर, मैसर्स द डो-कैमिकल् कंपनी यू०एस०ए० और मैसर्स बेयर पाल्यूथेन्स एशिया प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर से उत्तर प्राप्त हुए।

1. मैसर्स शेल ईस्टर्न पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर, का प्रतिवेदन निम्नप्रकार है:-

1. कि मैसर्स जैल ईस्टर्न पेट्रोलियम , प्रा० लि० सिंगापुर में केवल थोड़ी सी बिक्री की है जो निर्यात की तुलना बहुत ही कम है और उक्त उत्पाद का सामान्य मूल्य उत्पादन की लागत के आधार पर सुनिश्चित किया जा सकता है ।
2. कि उत्पादन की लागत के संबंध में सिंगापुर के उत्पादकों के पास कई लाभदायक स्थितियां हैं और वे अन्य उत्पादकों के साथ सामान्य सुविधाएं और संभारतंत्र को शेयर करते हैं ।
3. कि क्योंकि कंपनी भारत सहित एशिया प्रशान्त और अन्य क्षेत्रों में उक्त उत्पाद का निर्यात करती है और सिंगापुर के घरेलू बाजार में अपने कुल उत्पादन की एक न्यूनतम भाग की बिक्री करती है । अतः एस० ए० एंड जी प्रमारों और लाभ के साथ सिंगापुर में उक्त उत्पादों की उत्पादन की लागत को सामान्य मूल्य की निर्धारण करने के लिये जाने पर विचार किया जाए ।
4. कि भारत में उक्त उत्पादों का बाजार याचिका कर्ता की कुल अधिष्ठापित क्षमता से अधिक है । अतः उक्त उत्पाद का आयात बिल्कुल जरूरी और आवश्यक है ।
5. कि याचिकाकर्ता का मामला बहिर्निवेशित सूचना पर आधारित है जो सूचना पर पाटनरोधी जॉच की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं माना जा सकता ।
6. याचिका कर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना सटीक नहीं मानी जा सकती क्योंकि यह सूचना द्वितीय स्रोतों से प्राप्त हुई है और यह प्रमाणित नहीं है ।
7. कि याचिका कर्ता के लाभप्रदता पर प्राथमिक प्रभाव का कारण, उत्पादन संयंत्र के साथ जुड़ी लागत और कच्चे माल की लागत है । इसके अलावा यह भी तर्क दिया जाता है कि केवल एक अथवा दो सूचकों को द्रवात्मक क्षति होने का आरोप सिद्ध करने के लिये नहीं माना जा सकता ।
8. विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा में प्रयुक्त होने वाला विवरण बहुत ही स्थूल है ।
9. पोलियोल आक्साइड का उत्पादन करने की नई पद्धतियां हैं जो संबद्ध वस्तुओं के लिये सम्पोषित करती हैं । प्रत्येक पद्धति का अपने उत्पादन और आर्थिक गतिकी का एक अलग तरीका होता है । निर्यातक द्वारा प्रयोग में लाई जा रही प्रक्रिया का याचिकाकर्ता द्वारा

उपयोग में लाई जा रही क्लोरो हाइड्रिन प्रक्रिया की तुलना में लाभ की स्थिति है क्योंकि निर्यातक द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया प्रमुख कच्ची सामग्री अर्थात् प्रोपोलीन को और अधिक क्षमता के साथ अंतिम निर्मित उत्पाद बदलती है और इसमें अपव्यय भी कम होता है ।

(II) मैसर्स डो कैमिकल क०, यू०एस०ए० का प्रतिवेदन निम्नप्रकार है :-

1. कि मैसर्स एम०पी०एल० मास्त में इस उत्पाद में एकमात्र उत्पादक है और उनका तथाकथित स्पेक आरगेनिक लि० के अधिग्रहण करने का एक मात्र कारण एकाधिकार स्थापित करना है ताकि वे उपयोगकर्ताओं से जो कि सभी छोटे पैमाने के यंत्र से संबंधित है, शर्तें मनवा सकें ।
2. फ्लैक्सिबल स्लैब स्टॉक पोलियोल के लिये बाजार मांग 16200 एम०टी०पी०एम् है और यह 10 प्रतिशत - 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है । याचिकाकर्ताओं के पास छोटी क्षमताओं के संयंत्र है और वे विभिन्न उपयोग के लिये पालियोल के विभिन्न कोटियों को विनिर्माण करते हैं । याचिका कर्ता के एक मात्र और घरेलू उत्पादक होने के कारण याचिकाकर्ता की क्षमता नहीं है कि वह मांग को पूरा कर सके और अतः शेष मांग को आयात द्वारा सम्पूरित किये जाने की आवश्यकता है ।
3. याचिकाकर्ता के पास 37,000 एम०टी० पालियोल की अनुमोदित/ लाइसेंसड क्षमता है, तथापि, अपनी एकाधिकात्मक कार्यकलापों को जारी रखने के दृष्टि से उन्होंने अपनी क्षमता उपयोग में वृद्धि करने के लिये कोई सकारात्मक योगदान नहीं दिया है जिससे कि इस क्षेत्र के नये प्रवेशकों को निरुत्साहित किया जा सके ।
4. कि डो कंपनी के उत्पाद याचिकाकर्ता द्वारा विनिर्मित किये जाने वाले उत्पाद से अलग है । उक्त उत्पाद फ्लैक्सिबल पी०यू०फोम के विनिर्माण में प्रयोग में आता है । यह इस पी०यू० फोम का विनिर्माण मास्त में दो तरीकों से होता है अर्थात् कन्टीन्युअस फोर्मिंग और वाक्स फोर्मिंग में । यद्यपि वह कच्ची सामग्री जो इन दोनों तरीकों से प्रयोग में आती है, समान प्रकार की है, तथापि कन्टीन्युअस फोर्मिंग पद्धति में अधिक उत्पाद गुणवत्ता की आवश्यकता होती है और इससे भी अधिक आवश्यकता बैच दर बैच विनिर्देशों में संगति बनाये रखने की होती है ।
5. याचिकाकर्ता दावा करता है कि यह बात पूरी तरह से सत्य नहीं है कि इसके उत्पाद और आयातित उत्पाद और आयातित उत्पाद एक समान है । फ्लैक्सिबल स्लैब स्टॉक पालियोल में, प्रोपीलीन आक्साइड (पी०ओ०) के उपयोग के आधार पर अथवा इसका एथीलीन आक्साइड फंक्शनल ग्रुप ई०ओ० के संयोजन में होमो पोलिमर्स (केवल पी०ओ०) अथवा हीटरो पोलिमेर (ई०ओ० और पी०ओ० के संयोजक) बनाये जाते हैं । यह नोट करना उचित है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात किये जाने वाले दो पालियोल अथवा एफ०एस०पी०, हीटरो पालियोल है जबकि एम०पी०एल० द्वारा उत्पादन किये जा रहे अधिकतर उत्पाद होमो पॉलियोल हैं ।

6. पिछले तीन वर्षों के दौरान इन संबद्ध देशों से आयात की मात्रा में काफी कमी आई है कि याचिकाकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़े केवल सात महीने के लिये होते हैं जिन्हें उसके बाद हटा दिया जाता है। उत्पाद की बिक्री के अप्रैल, मई और जून महीने के मंदी अवधि होने के साथ चक्रीय होने के कारण बहिर्निवेशित आंकड़े बहुत ही अशुद्ध हैं और उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, याचिकाकर्ता की बहिर्निवेशित पद्धति को स्वीकार कर लेने पर भी संबद्ध आयातों में विशुद्ध मात्रा और बाजार शेयर दोनों के संदर्भ में कमी आई है। प्रत्येक अवधि के दौरान विषयगत आयातों में कमी आई है। दूसरी बात यह है कि याचिकाकर्ता द्वारा आंकड़े द्वितीयक स्रोतों से एकत्रित किये गये हैं जो वास्तविक अथवा प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों से मेल नहीं खा पायेंगे।

7. कि संयुक्त राज्य अमेरिका से संबद्ध आपातों से मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। भारत में पी.आई.ओ. के लिए आयातों का सी.एफ.आर. मूल्य पड़ोसी देशों में चल रहे मूल्यों के अनुरूप है।

8. कि याचिकाकर्ता ने सामान्य मूल्य निकालने के लिए बिल्कुल ही गलत आधार लिया है। याचिकाकर्ता के निर्यातक देशों के मूल्य आंकड़े, जो कि कई अभिकरणों के पास उपलब्ध है। एकत्र करने की असमर्थता निर्यातक देशों में उत्पाद की लागत निकालने की प्रक्रिया बना देते हैं। मूल्य आंकड़ों की अनुपलब्धता का याचिकाकर्ता का दावा बिल्कुल ही आधारहीन है।

9. कि याचिकाकर्ता की पी.ओ. विनिर्माण सुविधा का आकार इतना है कि बहार्थिक रूप से किफायती स्वीकार्य लागत पर पी.ओ. का उत्पादन नहीं कर सवा। यह बात नोट की जानी चाहिए कि पी.ओ. के लिए विश्व स्तर के सां 1,50,000 एम.टी. पी.ए. से अधिक क्षमता के होते हैं।

10. कि याचिकाकर्ता पिछले तीन वर्षों में 15 प्रतिशत का एक अच्छी मूल्य वृद्धि प्राप्त करने में सफल रहा है। बावजूद इसके कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पाद के मूल्यों में अपेक्षाकृत कोई वृद्धि नहीं हो रही है।

11. कि ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने विलयन पूर्व तत्व (प्रि-मर्जर एनटिटी) की सामान सूची को विलयन बाद के तत्व सूची के साथ तुलना की है और सामान सूची में वृद्धि आयात के कारण क्षति होने के समेत की बजाए तेजी और मंदी के मौसम में तुलना किए जाने के कारण है।

12. कि इस बात का कोई औचित्य नहीं है। औचित्यपूर्ण प्रमाण नहीं है कि एफ.एस.पी. के आयात द्वारा याचिकाकर्ता की लाभप्रदता प्रभावित हुई है।

13. कि याचिकाकर्ता की अपनी इन हाउस समस्याओं के कारण वह न तो अपने अंश में वृद्धि कर सकता है और न ही इसकी लाभप्रदता में यहां तक कि कथित पाटन में अनुपस्थिति में सुधार कर सकता है।

III. मैसर्स बेयर पालीस्थेन्स एशिया प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर का प्रतिवेदन निम्न प्रकार है -

1. कि अपने सबसे अधिक विश्वसनीय तकनीकों द्वारा समर्थन दिए जाने के साथ वे पिछले 25 वर्षों के लिए भारत में उक्त उत्पाद की नियमित रूप से आपूर्तिकर्ता है।
2. उनके उत्पाद भली भांति ज्ञात और स्थापित प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित होते हैं और भारतीय बाजार में उनकी सतत मांग है और वे भारत में स्लैब स्टॉक फोम मार्केट में सहर्ष स्वीकार्य होते हैं।
3. कि उनका भारतीय स्लैब स्टॉक पॉलिपोल बाजार को क्षति पहुंचाने का कभी भी आशय नहीं रहा है।
4. कि मौजूदा भारतीय फ्लैक्सिबल स्लैब स्टॉक पॉलिपोल बाजार का आकार प्रति वर्ष 16000 एमटी0 के आस पास है जो पिछले तीन वर्षों के लिए लगभग 11-12% की द्वि-अंकीय वृद्धि मांग को पूरा करने के लिए घरेलू उत्पादन की क्षमता पर्याप्त नहीं है, अतः कभी को आयातों के माध्यम से पूरा करना होता है।
5. कि घरेलू उत्पादक, मैर्सस मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड निरन्तर संरक्षण की मांग करता रहा है। उनके प्रचालनों की आर्थिक व्यवहार्यता, सक्षम उत्पादन प्रक्रिया और एक वृहत्तर आर्थिक उत्पादन क्षमता पर आधारित है। लेकिन दुर्भाग्यवश तीन वर्षों में इनमें से किसी को भी प्राप्त नहीं कर पाए हैं, वे बावजूद इस तथ्य के कि संरहित रक्षण उनके हक में लागू किये गये थे।
6. कि आर्थिक क्षेत्र में विश्व में एक सामान्य मंदी चल रही है और सामान्यतया लगभग सभी पॉलिमर्स के मूल्यों पर दबाव है भारत के लिए फ्लैक्सिबल स्लैब स्टॉक पॉलिपोल का मूल्य निर्धारण करने की प्रवृत्ति अनुकूल रूप से एशिया प्रशान्त क्षेत्र में प्रचलित मूल्य के बराबर अथवा इनसे अधिक रहे हैं और इस प्रकार उन्हें भारत में पाटन के विशेष मामले के रूप में परिलक्षित नहीं किया जा सकता है।
7. कि भारतीय बाजार में पहले ही एशिया प्रशान्त क्षेत्र में सबसे अधिक संरक्षण शुल्क है अर्थात् 35% मूल सीमा शुल्क जो अन्य स्रोतों के साथ मिलकर वास्तव में कुल मिलाकर 42% हो जाता है जबकि भारत में फ्लैक्सिबल स्लैब स्टॉक पॉलिपोल की प्रति व्यक्ति खपत इस क्षेत्र सबसे कम है अर्थात् चीन और अन्य विकसित देशों की तुलना में लगभग 1/20 है। संरक्षण में ओर कोई अन्य वृद्धि किए जाने से उपभोक्ताओं के लिए लागत में वृद्धि किए जाने से उपभोक्ताओं के लिए लागत में वृद्धि होगी और इस क्षेत्र में खपत वृद्धि/औद्योगिक वृद्धि इससे बाधित होगी।
8. कि घटती-बढ़ती विनिमय दरों के कारण भारत में होने वाला आयात भी प्रभावित हुआ है और इससे पिछले एक वर्ष में लगभग 5% का अतिरिक्त प्रभाव पड़ा है।
9. कि मनाली पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड एण्ड स्पिक ऑर्गेनिक को मिलाकर एक कम्पनी बना दिया गया है और जिसने एकाधिकारवादी रुख अपना लिया है बाजार में

प्रतिवादियों की उपस्थिति एकाधिकारवादी तरीकों को बाधित करती है और उचित मूल्य निर्धारण किए जाने की बात को प्रोत्साहित करके उपभोक्ताओं को संरक्षण देती है।

(ब) प्राधिकारी द्वारा जाँच और निष्कर्ष

9. आयातकों निर्यातकों उपयोगकर्ताओं, घरेलू उद्योगों और अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोध की उचित सीमा तक जाँच की गई है। इन निष्कर्षों को निकालते समय जो भी उचित पाया गया है उनपर विचार किया गया है तथा आगे जहाँ भी उचित पाया गया है उन पर कार्रवाई की गई है।
10. नये निर्यातकों अथवा उन निर्यातकों, जो कीमत संबंधी वचन पत्र देने के इच्छुक बताए गए हैं, के मामलों पर अनुरोध करने पर उपरोक्त नियमों के अनुसार प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा।

(च) विचाराधीन उत्पाद और सामान प्रकार की मदें।

11. इन जाँचों में विचाराधीन उत्पाद को "आणविक भार 3000 से 4000 तक का फ्लैक्सिबल स्लेब स्टॉक पॉलियोल" माना गया है। इन उत्पादों को सीमा शुल्क अधिनियम के अध्याय के शीर्ष 3907.20 के तहत वर्गीकृत किया गया है लेकिन इनका विवरण अध्याय शीर्ष 3907.91 और 3907.99 के तहत भी दिया गया है। निर्यातकों ने दावा किया है कि उत्पाद का विवरण काफी विस्तृत है तथापि, यह निर्दिष्ट करने के लिए पर्याप्त तर्क नहीं दिया गया है कि यह विवरण किसी भी उत्पाद को उस विवरण से अधिक कवर करता है जो याचिकाकर्ता द्वारा अभिप्रेत किया गया था और तत्पश्चात इसे जाँच के कार्यक्षेत्र के लिए स्वीकार किया गया। अतः प्राधिकारी विचार करता है कि विचाराधीन इस उत्पाद का यह विवरण बिल्कुल सही और स्टीक है इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि सीमा-शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वे मौजूदा जाँच के कार्यक्षेत्र पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।
12. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तुएं सम्बद्ध देशों के मूल की अथवा वहाँ से निर्यात होने वाली वस्तुओं के लिए समान वस्तु जैसी है। यह बात उठाई गई कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित यह उत्पाद और आयातित उत्पादों को सामान मद्धे के रूप में नहीं माना जा सकता है। फ्लैक्सिबल स्लेब स्टॉक पॉलियोल में, प्रोपीलीन ऑक्साइड के उपयोग अथवा इसमें, एथीलीन ऑक्साइड फंक्शनल ग्रुप के किसी संयोजन के आधार पर होमो पॉलिमर्स अथवा हीटरो पॉलिमर्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि यह नोट करना उचित है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात किए जा रहे अधिकतर पॉलियोल हीटरो पॉलियोल है जबकि एम0पी0एल0 द्वारा उत्पादित किए जा रहे अधिकतर होमो पॉलियोल हैं। इस मामले की प्राधिकारी द्वारा जाँच की गई है। निर्यातक का मूलभूत आपत्ति यह है कि पॉलियोल

आक्साइड जो कि संबद्ध विषयगत सामान के उत्पादन के लिए एक मुख्य फीड स्टॉक है, विभिन्न पद्धतियों द्वारा प्राप्त किया जाता है और अतः परिणामात्मक एफओएसपीओ को समान मद के रूप में नहीं माना जा सकता है। यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि यह निर्धारित करने की जांच में कि क्या कोई दो उत्पाद सामान वस्तुएँ हैं अथवा नहीं, अन्य बातों के साथ-साथ क्या वह निर्धारण किया जाना शामिल होता है कि क्या दो उत्पाद तकनीकी और वाणिज्य रूप से प्रतिस्थापनीय हैं अथवा नहीं इस बात के लिए कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामान और वह सामान जिसका भारत में आयात किया जा रहा है समान प्रकार की वस्तुएँ नहीं हैं के लिए कोई तर्क नहीं दिए गए हैं अथवा अपने तर्क को सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण नहीं दिये गये हैं। अतः प्राधिकारी ने निर्धारित किया है कि आयात की जा रही वस्तुएँ विचाराधीन उत्पाद के लिए समान प्रकार की वस्तुएँ हैं।

छ. घरेलू उद्योग

13. मैसर्स मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (मपीओएलओ) द्वारा जो कि देश में संबद्ध वस्तु के एक मात्र उत्पादक हैं, याचिका दायर की गई है। अतः घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर करने के लिए उनका दावा बनता है। इसके अलावा याचिकाकर्ता संबद्ध उत्पाद के किसी भी आयात/निर्यात से संबंधित नहीं है। याचिकाकर्ता उक्त नियमों के नियम 5(3) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर करने के आधार संबंधी मापदण्ड को पूरा करते हैं।

ज. सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन

14. प्राधिकारी ने धारा 9(क)(1)(ग) के अनुसार सामान्य मूल्य के निर्धारण के उद्देश्य से सभी ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी तथापि यूरोपीय संघ और जापान के किसी भी निर्यातक ने न तो उत्तर भेजा और न ही उन्होंने कोई सूचना दी। अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि यूरोपीय संघ और जापान के किसी भी निर्यातक ने प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है जैसा कि नियमों के तहत अपेक्षित था और उनके मामले में नियम 6(8) लागू होता है।
15. प्राधिकारी ने पाया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्यातक अर्थात् मैसर्स "द डो कैमिकल्स कम्पनी, जिन्होंने कि अपनी टिप्पणियाँ भेजी हैं, ने इस निदेशालय को निर्धारित प्रोफार्मा में अपना उत्तर नहीं भेजा है। इसके अलावा उन्होंने यहाँ तक की कोई ऐसी सूचना नहीं भेजी है जिसे कि जाँचों में उपयोग में लाया जा सकता हो। निर्यातक ने सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और न ही उत्पादन की लागत के संबंध में बिना किसी प्रकार की सूचना देते हुए केवल कुछ रिपोर्ट ही प्रस्तुत की हैं। पृष्ठक पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए उक्त निर्यातक को असहयोगी पाया गया है और प्राधिकारी इस निर्यातक के लिए व संयुक्त राज्य अमेरिका से अन्य निर्यातकों के लिए उपरोक्त नियम 6(8) के अनुसार अपने पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर निष्कर्ष निकालेंगे।

16. सिंगापुर से दो निर्यातकों अर्थात् मैसर्स बेयर पॉलीयुथेन्स एशिया प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स शैल ईस्टर्न पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने अधिसूचना जारी किए जाने के प्रति उत्तर दिया है। मैसर्स बेयर के सम्बन्ध में निर्यात मूल्य, घरेलू बिक्री मूल्य, उत्पादन लागत, माल भाड़ा, बीमा क्रेडिट बिक्री, छूट, आदि के बारे में समायोजना के संबंध में कोई विवरण निर्धारित फॉर्मेट में नहीं दिया गया है। मैसर्स शैल ईस्टर्न पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड जिन्होंने उत्तर दायर किया है, के संबंध में यह पाया गया है कि उक्त निर्यातक प्रश्नावली के परिशिष्टों के प्रति कोई अगोपनीय सूचना देने में असफल रहा है। इसके अलावा इस निर्यातक ने अपनी बिक्री/क्रेडिट प्रबन्ध, अधिष्ठापित क्षमता और अन्य वस्तुओं का उत्पादन, उत्पादन के लिए संयंत्र का आवंटन और मशीनरी, अपनी उत्पादन लागत/निर्यात बिक्री के संबंध में व्याज आदि का कोई ब्यौरा नहीं दिया है। उत्पादन की लागत में फाइनेन्स चार्ज का किसी भी प्रकार का संकेत नहीं है जबकि तुलन पत्र दर्शाता है कि कम्पनी का इस मद पर व्यय हुआ है। विचाराधीन उत्पाद और अन्य उत्पादों की बिक्री के संबंध में समाधान नहीं दिया गया है जैसाकि परिशिष्ट 3 और 7 के लिए अपेक्षित है। कम्पनियों के संबंध में विशेषकर कि व्यापारिक/विनिर्माण करने वाली कम्पनियों के सम्बन्ध में सूचना नहीं दी गई है अतः यह पाया गया है कि निर्यातक द्वारा दिए उत्तर को एक पूरा उत्तर नहीं माना जा सकता है। अतः प्रारम्भिक निष्कर्षों के उद्देश्य के लिए प्राधिकारी ने सिंगापुर से सभी निर्यातकों के मामलों में उपरोक्त नियम 6 (8) के अनुसार उपलब्ध सूचना को उपयोग में लाने का निर्णय किया है। तथापि, मैसर्स शैल ईस्टर्न पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर द्वारा दिए गए निर्यात मूल्य और दावा किए गए समायोजन के बारे में सूचना को उनके मामले में पाटन मार्जिनों की गणना करने के उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया गया है।
17. निर्यातकों/आयातकों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आयातकों के सम्बन्ध में घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना को परिशुद्ध नहीं माना जा सकता क्योंकि यह सूचना द्वितीयक क्षेत्रों से प्राप्त की गई है। डी0जी0सी0आई0 एण्ड एस0 से आंकड़ों की उपलब्धता की उपस्थिति में नामित प्राधिकारी सतत रूप से उन्हें अन्य स्रोतों से भी उपलब्ध कराई गई सूचना पर अनुकूल रूप से भरोसा करते रहे हैं। यह पद्धति समग्र रूप से कानूनी स्थिति के अनुरूप है। तथापि, विस्तृत जाँच के एक भाग के रूप में प्राधिकारी पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए निर्यात की मात्रा और उसका मूल्य निकालने के लिए एवं क्षति आंकलन के लिए भागीदारी करने वाले निर्यातकों/आयातकों से प्राप्त सूचना को उपयोग में ला रहे हैं। उपलब्ध सूचना के आधार पर निवल निर्यात मूल्य निकालने के लिए माल भाड़ा, समुन्द्री बीमा, कमीशन, पतन सम्माल (पोर्ट हैंडलिंग) के कारण और समायोजन दिए गए हैं।
18. सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन जैसा कि सीमा शुल्क टेरिफ अधिनियम में दिया गया है, के निर्धारण को अधिशसित करते हैं और पाटन रोधी नियमों का ब्यौरा, नियमों के अनुबंध - 1 में दिया गया है। प्रारम्भिक निष्कर्षों के उद्देश्य के लिये निकाला गया पाटन मार्जिन निम्नप्रकार से है -

देश/ संघ शासित	निर्यातक/ निर्माता	पाटन मार्जिन प्रतिशत
यूएसएसए	सभी निर्यातक	46.01
जापान	सभी निर्यातक	42.19
यूरोपीय संघ	सभी निर्यातक	38.60
सिंगापुर	सभी निर्यातक	32.27

अ. क्षति

19. पाटनसेवी नियमावली के नियम 11 में निम्नानुसार व्यवस्था है:

क्षति का निर्धारण:

- (i) विनिर्दिष्ट देशों से हुए आयातों के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी आगे अपने निष्कर्ष दर्ज करेगा कि भारत में होने वाले ऐसे आयातों से भारत में स्थापित किसी उद्योग को वास्तविक क्षति होती है अथवा क्षति का खतरा उत्पन्न होता है अथवा किसी उद्योग को स्थापित करने में अत्यधिक बाधा आती है ;
- (ii) निर्दिष्ट प्राधिकारी घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति, घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के खतरे और घरेलू उद्योग की स्थापना में आने वाली अत्यधिक बाधा और पाटित आयातों एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का निर्धारण पाटित आयातों की मात्रा, घरेलू बाजार में समान वस्तुओं की कीमतों पर इसके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव समेत सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और इन नियमों के अनुबंध- II में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार करेंगे ।"

20. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय यह जांच करना जरूरी माना गया है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों में भारी कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों में अन्यथा महत्वपूर्ण स्तर तक कमी करना है । भारत में घरेलू उद्योग पर प्रभाव की जांच के लिए प्राधिकारी ने ऐसे और कारकों पर विचार किया है जोकि घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालते हैं यथा उत्पादन, बिक्री स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति इत्यादि ।

क्षति का सकल आकलन

21. रिकार्ड में तथ्यों के आधार पर यह पाया गया है कि प्रत्येक सम्बद्ध देश से पाटन का मार्जिन 2 प्रतिशत की सीमा से अधिक होता है, जिसे निर्यात के प्रतिशत में दर्शाया जाता है । प्रत्येक इन देशों से आयात की मात्रा भी न्यूनतम से अधिक होती है । आयातों के प्रभावों का सकल आकलन भी उचित होगा क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात एक दूसरे देश से और मास्तीय बाजार में सीधे एक दूसरे से प्रतिस्पर्द्धा करते हैं

अतः प्राधिकारी संबंध देशों से सकल रुप से घरेलू उद्योग को हो सकने वाली क्षति को आंकने का प्रस्ताव करता है ।

संबद्ध देशों से आयातों का बाजार अंश -

22. निम्नलिखित सारणी से देखा जा सकता है कि कुल आयातों के एक प्रतिशत के रुप में संबंध देशों से आयातों का बाजार अंश, जांच की अवधि के दौरान वर्ष 1999-2000 की 83.72 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 91.73 प्रतिशत हो गया है । चूंकि सभी आयातकों अथवा निर्यातकों ने निर्धारित प्रोफार्मा में सूचना नहीं दी गई अतः इस बात की काफी संभावना है कि यदि आईसीटीडी से विशेषकर कि दिल्ली और काठला में बल्क शिपमेंट आयातों की वास्तविक मात्रा और अधिक ऊंची हो सकती है ।

संबद्ध देशों से आयातों का बाजार अंश - (कुल आयातों का प्रतिशत)

वर्ष	संबद्ध देश से आयात (एम0 टी)	कुल आयात	प्रतिशत शेयर
1998-99	2350.12	2383.72	98.59 प्रतिशत
1999-2000	1983.15	2368.65	83.72 प्रतिशत
अक्तू 2000 जून 2001	1631.97	1779.97	91.73 प्रतिशत

संबद्ध देशों से आयातों का बाजार अंश (कुल मांग का प्रतिशत)

23. जैसाकि निम्नलिखित सारणी से दृष्टिगत होगा कि कुल मांग के अनुपात के रुप में संबंध देशों से आयातों का बाजार अंश 1999-2000 के 19.43 प्रतिशत से तेजी से बढ़कर जांच की अवधि के दौरान 22.08 प्रतिशत हो गया है ।

वर्ष	आयात (एम0टी0)	कुल मांग	प्रतिशत शेयर
1998-1999	2350.12	8900.58	26.40 प्रतिशत
1999-2000	1983.15	10207.21	19.43 प्रतिशत
अक्तूबर 2000 जून 2001	1631.97	7390.16	22.08 प्रतिशत

उत्पादन और क्षमता उपयोग

24. यह बात देखी गई है कि जांच की अवधि के दौरान उत्पादन और घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग में कुछ वृद्धि होने के बावजूद भी घरेलू उद्योग ने बहुत कम मूल्य प्राप्ति के कारण हानि उठाई है । अतः यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग वित्तीय मापदंडों पर

नुकसान कीमत पर ग्राहक और बाजार अंश को रोक पाई । इस प्रकार उत्पादन में प्रत्यक्ष वृद्धि और क्षमता उपयोग को पाटित आयातों के मूल्य प्रभाव के संदर्भ में देखा जाना होता है ।

वर्ष	क्षमता (एम0टी0)	उत्पादन (एम0टी0)	क्षमता उपयोगिता प्रतिशत
1998-99	***	***	***
1999-2000	***	***	***
अक्तू 2000- जून 2001	***	***	***

बिक्री की मात्रा और घरेलू उद्योग का मूल्य

25. जहां तक बिक्री मूल्यों का संबंध है इनमें पिछले वर्ष की तुलना में कुछ सीमांतिक वृद्धि हुई है लेकिन घरेलू उद्योग द्वारा यह दावा किया गया है कि मूल्यों की इस वृद्धि का कारण झालर की तुलना में रुपये का गिरना और प्रमुख कच्ची सामग्रियों और ईंधन की लागत में वृद्धि होना है । यह बात इस तथ्य में भी परिलक्षित होती है कि बिक्री मूल्यों में सीमांतिक वृद्धि होने के बावजूद भी हानियों में और वृद्धि हुई । साथ ही घरेलू उद्योग का यह दावा है कि घरेलू उद्योग के लिये यह संभव नहीं है कि कच्ची सामग्री के मूल्यों में वृद्धि होने के बावजूद भी सटीक तौर पर पाटन के कारण वे अपने मूल्यों में वृद्धि कर सकें । अतः सम्बद्ध देशों से पाटन के कारण मूल्यों में कमी होने के पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं ।

वर्ष	विक्रय मूल्य (एम0टी0)	विक्रय मूल्य (लाख रु में)	यूनिट लागत (रु0/एम0टी0)
1998- 1999	***	***	***
1999-2000	***	***	***
अक्तू2000 जून 2001	***	***	***

लाभप्रदता

26. घरेलू उद्योग के रिकार्डों की जांच दर्शाती है कि घरेलू उद्योग बिक्री की प्रति यूनिट सीधी बिक्री के रूप में भारी क्षति हुई है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यह मूल्य घटक ही है जिसे घरेले मूल्य घटक ही है जिसे घरेलू उद्योग को व्यापक क्षति होने का कारण समझा जा सकता है और जिसके परिणाम स्वरूप क्षमता उपयोग एवं उत्पादन में सुधार होने के बावजूद हानियां हुई हैं ।

वर्ष	विक्रय मूल्य लाख रु में	विक्रय का मूल्य लाख रु में	लाभ/ यूनिट
1998-1999	***	***	***
1999-2000	***	***	***
अक्टू 2000-जून 2001	***	***	***

मूल्यों में कमी

27. यह दावा किया गया है कि सम्बन्धित देशों द्वारा किये जा रहे पाटन से घरेलू उद्योग द्वारा सम्बद्ध वस्तु के लिये निम्न विक्री प्राप्ति पर काफी प्रभाव पड़ा है अपने बाजार अंश को बनाये रखने के लिये प्राधिकारकर्ताओं को सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तुओं से कम किये गये मूल्यों और पाटन के साथ प्रतिस्पर्द्धा करनी पड़ रही है। पाटित आयातों की पहुँच मूल्य भी यह निर्दिष्ट करता है कि मूल्यों में कमी हो रही है।

कम मूल्य पर बेचना

28. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के इस दावे की जाँच की है कि घरेलू उद्योग को सीधी क्षतियों के कारण हानि हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति को आँकने के लिये मूल्य से कम मूल्य पर विक्री करना एक महत्वपूर्ण संकेतक है। प्राधिकारी ने एक उचित विक्री मूल्य तैयार किया है और कम मूल्य पर विक्री मूल्य का निर्धारण करने के लिये उसकी लदान मूल्य के साथ तुलना की है।

रोजगार

29. रोजगार के आँकड़े की क्षति का प्रभाव दिखाते हैं क्योंकि बावजूद इस तथ्य के ही मीजूदा श्रमिक कानूनों के कारण सामान्य जनशक्ति में कमी करना संभव नहीं हो पाता है। रोजगार स्तर में लगभग 7 प्रतिशत की कमी हुई है।

सामान सूची में वृद्धि

30. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि भारी पाटन के कारण वह बाजार में अपने उत्पादों की विक्री करने में समर्थ नहीं हो पाई है। यह इस तथ्य से भी दृष्टिगत होता है कि दो संयंत्रों में से एक ने सामान सूची 31-3-2000 की स्थिति के अनुसार *** एम0टी0 से बढ़कर जून 2001 में *** एम0टी0 हो गई है, जो कि तीन गुणा से अधिक की वृद्धि है। इसके अलावा, इन्हें पहले ही सामान सूची के भारी एकत्रीकरण के कारण अपने उत्पादन में कमी करनी पड़ी है। दूसरे संयंत्र में सामान सूची भी *** एम0टी0 के बहुत ही अधिक स्तर पर है। दोनों संयंत्रों को लेते हुए सामान सूची में समग्र वृद्धि वर्ष 1999-2000 की तुलना में जाँच की अवधि के दौरान 61 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है।

31. साक्ष्य की जाँच करने पर यह पाया गया है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्रियों और क्षमता उपयोग में कुछ वृद्धि हुई है। तथापि, संबद्ध देशों से कम मूल्यों पर और पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हानियाँ हो रही है। प्राधिकारी के पास उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार क्षति उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार क्षति बताने वाला सबसे अधिक महत्वपूर्ण मापदंड मूल्यों में कमी का होना है।

आयातों की मात्रा में तुलनात्मक और निबिल रूप में वृद्धि हुई है। उपर्युक्त तथ्य स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग द्वारा उठाई जा रही क्षति को दर्शाते हैं। प्राधिकारी के पास उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार यह निर्धारित किया गया है कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है और जाँच की अवधि के दौरान इसे और क्षति होने का खतरा है।

ज. कारणात्मक संबंध -

32. यह निर्धारित करने के लिये कि क्या घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण क्षति हुई थी। प्राधिकारी ने निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखा है -

- क. पाटित मूल्यों पर संबद्ध देशों से काफी मात्रा में आयातों से घरेलू उद्योग को हानियाँ हुई हैं।
- ख. प्राधिकारी ने यह भी देखा है कि सम्बद्ध वस्तुओं के लिये केवल एक ही बाजार है जहाँ पाटित आयात घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं। सम्बद्ध फलैक्सिबल पालियोल के लिये मांग एक अच्छी वृद्धि दर्शा रही है। अतः मांग में कमी घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने वाला कारण नहीं है। आयातित उत्पाद उसी प्रकार के वाणिज्यिक ग्रेडों और मानक विनिर्देशों को पूरा करने के लिये बेचे जाते हैं, जैसाकि घरेलू रूप से उत्पादित पालियोल। आयातित सम्बद्ध सामान और घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुएँ समान प्रकार की मर्दे हैं और उन्हें समान उद्देश्यों/प्रयोगों के लिये उपयोग में लाया जाता है। इस प्रकार मूल्य निर्धारण की बात आयातित स्रोतों से अथवा घरेलू स्रोतों से सामान की खरीददारी का निर्धारण करने के लिये एक महत्वपूर्ण घटक है।
- ग. सम्बद्ध देशों से किये गये आयातों से भारतीय बाजार में उत्पादों के मूल्यों को इस सीमा तक कम किया है कि घरेलू उद्योग को अपने उत्पादन की लागत को वसूल नहीं कर पाया है और भारत में सम्बद्ध वस्तुओं की बिक्री से एक औचित्यपूर्ण लाभ नहीं ले पाया है।

ट. भारतीय उद्योग का हित

33. सामान्य तौर पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य ऐसे पाटन को समाप्त करना है जिससे भारतीय उद्योग को नुकसान हो रहा है तथा भारतीय बाजार में ऐसी खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की पुनः बहाली करना है जो कि देश के सामान्य हित में है।
34. प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध वस्तु के उपयोग से विनिर्मित उत्पादों के कीमत स्तर प्रभावित होंगे और परिणामस्वरूप इन उत्पादों के तुलनात्मक प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रभाव पड़ सकता है किन्तु पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत पाटनरोधी उपायों को लागू करके पाटन द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे, भारतीय उद्योग का ह्रास रुकेगा और संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपायों से सम्बद्ध देशों से आयात किसी भी प्रकार कम नहीं होंगे, इसलिए उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उपभोक्ता अभी भी दो या इससे अधिक आपूर्ति के स्रोत रख सकेंगे।

ठ. अन्य मुद्दे -

35. आयातकों, निर्यातकों और कुछ हितबद्ध दलों द्वारा यह दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता अर्थात् एमपीओ एल देश से संबद्ध वस्तुओं के एकमात्र उत्पादक है और अतः वर्तमान प्राधिकार उनके द्वारा भारत में एक एकाधिकार उत्पादक के रूप में उनकी स्थिति को सुदृढ़ करने और किसी प्रतिस्पर्द्धा को टालने के लिये दायर की गई है। इसके अलावा याचिकाकर्ता की कुल क्षमता देश में एफ एस पी की मांग से बहुत ही कम है और संयंत्रों का आकार भी अलाभकारी है। यह भी तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रयुक्त प्रोद्योगिकी पुरानी और घटिया है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के बारे में एवं एफ एस पी के उत्पादन के लिए निर्धारित लागत और परिवारों के आबंटन के लिये अपनाई गई पद्धति के बारे में भी मुद्दे उत्थये गये हैं। यह भी उल्लेख किया गया है कि एफ. एस. पी. सहित सभी कैमिकल्स और प्लास्टिक्स के अन्तराष्ट्रीय मूल्यों ने पिछले कुछ वर्षों में कमी की प्रवृत्ति दर्शाई है और भारत को निर्यात के मूल्य, अन्तराष्ट्रीय बाजार में व्याप्त मूल्यों पर हैं। आयातकों और उपयोगकर्ताओं द्वारा अपने प्रतिवेदन में यह भी दिया गया है कि संबद्ध वस्तुओं पर सुस्ला शुल्क दिनांक 17-9-1998 के अंतिम निष्कर्षों द्वारा लगाये गये थे और घरेलू उद्योग, अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिये निदिष्ट प्राधिकारी की मशीनरी का जान बूझकर दुरुपयोग करने का प्रयास कर रहा है।

36. उपर्युक्त मुद्दों की प्राधिकारी द्वारा जांच की गई है। पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पाटन के कारण घरेलू उद्योग को होने वाली किसी भी क्षति को पर्याप्त रूप से देखा जा सके। यह तथ्य की देश में संबद्ध वस्तुओं का एक ही उत्पादक है, यह बात पाटनरोधी नियमों के तहत पाटित आयातों के प्रति निदिष्ट प्राधिकारी से राहत का दावा करने के लिये घरेलू उत्पादकों के अधिकार को किसी भी

प्रकार बाधित नहीं करती । यह एक स्वीकार्य स्थिति रही है कि पाटनरोधी शुल्क, प्रकृति और आकार में पाटन व्यापार के तोड़-मोड़ तरीकों के प्रति उपचारात्मक है । इसके अलावा पाटनरोधी शुल्कों का उद्देश्य किसी भी स्रोत से आयातों को सीमित करने अथवा रोकने का नहीं है और अतः घरेलू पूर्ति के देश में कुल खपत से कम होने के मामले की कोई प्रासंगिकता नहीं है, क्योंकि भारतीय औद्योगिक उपयोगकर्ताओं को पूर्ति के बैकल्पिक स्रोत भी उपलब्ध हैं । अतः याचिकाकर्ता कंपनी जो कि ग्राहकों का दोहन करने के लिये एकाधिकार की स्थिति को उपयोग में ला रही है, की शंका अनुचित है । विचाराधीन उत्पाद के लिये नियत लागत और अन्य प्रभासों का निर्धारण करते समय प्राधिकारी पर्याप्त सावधानी बस्ती गई है । सुस्त्रा शुल्क, जो विगत वर्षों में संबद्ध वस्तुओं पर लगाया गया है, के संबंध में प्राधिकारी का मत है कि घरेलू उद्योग पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि वे पाटित आयातों पर केवल इसलिए संरक्षण प्राप्त करे कि ऐसी वस्तुओं को विगत वर्षों में सुस्त्रा शुल्क प्राप्त था । भारत को निर्यात मूल्यों के, व्याप्त अन्तराष्ट्रीय मूल्यों के बराबर होने के विषय के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक देशों में सामान्य मूल्य और भारत को संबद्ध वस्तुओं के किये जाने वाले निर्यात मूल्यों से संबंधित होता है तथा सामान्य मूल्य का निर्धारण करते समय यह स्थापित किया गया है कि बिक्रियां, व्यापार के सामान्य रूप में हों ।

ब. निष्कर्ष

37. पूर्वोक्त पर विचार करने के पश्चात् प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि:
 - i) संबद्ध देशों से भारत को फ्लैक्सिबल स्लैब स्टॉक पोलियाल का निर्यात, जैसाकि विचाराधीन बात से संबंधित उपर्युक्त पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है, इसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है;
 - ii) भारतीय उद्योग की क्षति हुई है ;
 - iii) क्षति संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण हुई है;
38. प्राधिकारी घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त करने के उद्देश्य से अंतिम निर्धारण होने तक संबद्ध देशों से फ्लैक्सिबल स्लैब स्टॉक पोलियाल के सभी आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक समझते हैं । प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन उपरोक्त पैराग्राफों में दर्शाया गया है । प्राधिकारी पाटन के मार्जिन के बराबर अथवा उससे कम पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने का प्रस्ताव करते हैं जिसे यदि लगाया जाता है तो इससे घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति समाप्त हो जाएगी । क्षति का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना जांच अवधि के लिए निर्धारित याचिकाकर्ता कंपनियों की क्षति रहित बिक्री कीमत के साथ करने का प्रस्ताव है ।
39. तदनुसार प्राधिकारी सिफारिश करते हैं कि अंतिम निर्धारण होने तक संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पादों के सभी आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से अनंतिम पाटनरोधी

शुल्क लगाया जाए। पाटनरोधी शुल्क निम्नलिखित सारणी के कालम 3 में निर्दिष्ट मूल्यों और संबंधित आयातों के पहुंच मूल्य का अन्तर होगा: -

देश/क्षेत्र	निर्यातक/उत्पादक	घनराशि प्रति एमटी0 अमेरिकी डॉलर
(1)	(2)	(3)
संयुक्त राज्य अमेरिका	सभी निर्यातक	1804
जापान	सभी निर्यातक	1804
यूरोपीय संघ	सभी निर्यातक	1804
सिंगापुर	सभी निर्यातक	1804

40. इस उद्देश्य के लिए आयातों का पहुंच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमाशुल्क द्वारा यथा आकलित निर्धारणीय मूल्य होगा और उसमें सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 एवं 9क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सभी सीमाशुल्क शामिल होंगे।

ढ. आगे की प्रक्रिया

41. प्रारंभिक निष्कर्षों को अधिसूचित करने के बाद निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा:-

- (क) प्राधिकारी सभी हितबद्ध पार्टियों से इन निष्कर्षों के बारे में टिप्पणियां आमंत्रित करेंगे और उन पर अंतिम निष्कर्षों में विचार किया जाएगा।
- (ख) प्राधिकारी द्वारा निर्यातकों, आयातकों याधिकाकर्ताओं तथा अन्य ज्ञात हितबद्ध पार्टियों को अलग से लिखा जा रहा है जो प्रारंभिक निष्कर्षों की तारीख से 40 दिनों के अंदर अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई अन्य हितबद्ध पार्टी भी इन निष्कर्षों के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों के भीतर अपने विचारों से अवगत करा सकती है।
- (ग) प्राधिकारी सभी हितबद्ध पार्टियों को मौखिक अनुरोध करने के लिए अवसर प्रदान करेंगे जिन्हें बाद में लिखित में प्रस्तुत करना होगा।
- (घ) प्राधिकारी यथोचित सीमा तक आगे जांच करेंगे।
- (ङ.) अंतिम निष्कर्षों की घोषणा करने से पहले प्राधिकारी आवश्यक तथ्यों का प्रकट करेंगे।

एल.बी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December, 2001

PRELIMINARY FINDINGS

Subject :—Anti-dumping investigation concerning imports of the Flexible Slabstock Polyol of molecular weight 3000 to 4000 originating in or exported from the USA, Japan, European Union and Singapore—Preliminary findings.

No. 41/1/2001-DGAD.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof;

A. PROCEDURE

2. The procedure described below has been followed:-

- i The Designated Authority (hereinafter referred to as Authority), under the above Rules, received a written petition from M/s Manali Petrochemicals Ltd. (MPL), on behalf of the domestic industry, alleging dumping of Flexible Slabstock Polyol of Molecular Weight 3000 to 4000 (hereinafter referred to as subject goods or FSP) originating in and exported from USA, Japan, Singapore and territory of European Union (hereinafter referred to as subject countries);
- ii) The Authority notified the Embassies/Representative of the subject countries in India about the receipt of dumping application made by the petitioner before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 *supra*;

- iii) The Authority issued a Public Notice dated 21st September, 2001 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti dumping proceedings concerning imports of Flexible Slabstock Polyol falling under Chapter Heading 39.07 of the Customs Tariff Act.
- iv) The Authority forwarded copy of the said public notice to the known exporters, importers, users, industry associations and to the complainants and gave them an opportunity to make their views known in writing.
- v) According to sub-rule (3) of Rule 6 *supra*, the Authority provided a copy of the petition to all the known exporters and Embassies of subject countries in India.
- vi) The Authority sent questionnaires, to elicit relevant information, to the following exporters from the subject countries:
 - 1. M/s. SHELL EASTERN PETROLEUM (PTE) LTD., SINGAPORE – 239 920
 - 2. M/s. BAYER POLYURETHANE ASIA (PTE) LTD, SINGAPORE - 189 721.
 - 3. M/s. SANYO CHEMICALS, JAPAN.
 - 4. M/s. BAYER POLYURETHANE ASIA (PTE) LTD, GERMANY.
 - 5. M/s. REPSOL QUIMICA S.A., SPAIN.
 - 6. M/s. THE DOW CHEMICAL COMPANY, TEXAS – 77541, USA.
 - 7. M/s. THE DOW CHEMICAL COMPANY, TEXAS – 775720-585, USA.
- vii) The Embassies/representative of subject countries in New Delhi were also informed about the initiation of investigation and were requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time;
- viii) The questionnaire was sent to the following users/importers of subject goods:
 - 1. M/s Aagosh Polystyrene Foam Pvt. Ltd., Chandigarh.
 - 2. M/s Arvind International Ltd., Calcutta.
 - 3. M/s Banmore Foam Pvt. Ltd., Banmore, Distt: Morena (M.P.)

4. M/s Cozy Foams Pvt. Ltd, Chantupada, Palghar Thana
5. M/s D P Foam Pvt. Ltd., Pondicherry – 605 101
6. M/s Dura Foam Inds Pvt. Ltd., DADRA NAGAR, HAVELI
7. M/s Diana Foams Pvt. Ltd., ORISSA - 757 043
8. M/s Devi Polyurethane Pvt. Ltd., Tondedumala, Taligatpuri
DIST-NASIK
9. M/s Inkay Foam Pvt.Ltd., Village Khekra, Tehsil Baghpat
Distt. MERRUT (UP)
10. M/s Feather Foam Enterprises Pvt. Ltd., NOIDA – 201 301
11. M/s Foam House (India) Pvt. Ltd., MIDC Talao
MAHARASHTRA
12. M/s Feather Foam Enterprises Pvt. Ltd.,
SILVASSA
13. M/s Joy Foam Pvt. Ltd., Ranipet.
14. M/s Juhi Foam Pvt. Ltd., KHARAR (P.B.) – 140 031
15. M/s Kurlon Ltd., Bhubaneshwar – 751 031
16. M/s Kamal Foam, Pondicherry – 605 009
17. M/s M R Foams, Hyderabad
18. M/s Multiwyn Foams Pvt. Ltd., Calcutta – 700 016
19. M/s Modern Foam Udyog, VillageKakka, Ludhiana
20. M/s N L Foam Industries, Ahmedabad
21. M/s Natson Foam Mfg. Pvt. Ltd., Village - Nandoli
District Mehsana
22. M/s Panama Polystyrene Products Pvt. Ltd., Ghaziabad
23. M/s Pallivi Foam Inds. Pvt. Ltd., Noida-Dadri Road (U.P)
Distt: Ghaziabad
24. M/s Poly Foam, Chantupada, Distt: Thana

25. M/s Prabhat Polyurethane P. Ltd., Pondicherry.
26. M/s Pratap Polyurethane P. Ltd., Calcutta-700 001.
27. M/s P.U. Foam Pvt. Ltd., Calcutta – 700 007.
28. M/s Raj Leather Cloth Inds. Pvt. Ltd., Distt; Sonapat.
29. M/s Sheela Foam Pvt. Ltd., Ghaziabad, U.P. – 201 101.
30. M/s SSF Industries Ltd., Patna – 800 004.
31. M/s Sheela Foam Pvt. Ltd., Kalol Talukakadi, Noida (UP).
32. M/s Tirupati Foam Ltd., Distt. Mehsana
33. M/s Tirupati Foam Ltd., Taluk Kalol
34. M/s U. Foam Pvt. Ltd., Hyderabad-500 018.
35. M/s Surya Foam, Pondicherry
36. M/s Aparna Polyproducts Ltd., Jaipur - 302 001 (Rajasthan).
37. M/s Soft Foam Industries Pvt. Ltd., Medchol Ind. Area, RR District 501 401 (AP).
38. M/s Madras Polymoulds, Mylapore, Chennai-4.
39. M/s J.J. Foams Pvt. Ltd., Distt; Ghaziabad (UP).
40. M/s M H Polymers Pvt. Ltd., Dadri, Distt. Ghaziabad, U.P.
- ix) A number of importers/users have filed response to the Initiation Notification. M/s Shell Eastern Petroleum (Pte.) Ltd., Singapore, M/s Bayer Polyurethanes Asia Pte. Ltd., Singapore and M/s The Dow Chemical Co., USA among the exporters have responded to the Initiation Notification .
- x) The Authority kept available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file maintained by the Authority and kept open for inspection by the interested parties;
- xi) ***** in this notification represents information furnished by the interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules;
- xii) The investigation covered the period from 1st October, 2000 to 30th June, 2001;

- xiii) Copies of initiation notice was also sent to FICCI, CII, ASSOCHAM etc., for wider circulation.

B. PETITIONER'S VIEWS

3. The petitioners have made the following major points in their submissions:

- i. They are the only producers of the subject goods. Therefore, they have the standing to file the application on behalf of the domestic industry. Further, the petitioners are not related to any importer/exporter of the subject product.
- ii. There is no known difference in Flexible Slabstock Polyol produced by the Indian industry and Flexible Slabstock Polyol exported from Subject countries. Flexible Slabstock Polyol produced by the Indian industry and imported from subject countries are comparable in terms of physical as well as chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. Flexible Slabstock Polyol produced by the petitioners and imported from subject countries should be treated as like article in accordance with the anti-dumping Rules.
- iii. The exporters from subject countries have booked orders for significant quantity through their Indian agents. Significant material has already landed at the Indian ports and substantial material is understood to be in transit. The domestic industry is incurring huge losses and should the present trend of imports at dumped prices continue, the domestic industry may have to close their facilities.
- iv. The landed price of the imported material is significantly below the selling prices of the domestic industry. Further, should the exporters from the subject countries continue to offer the material at the present prices, the domestic industry would be compelled to reduce their prices further and lose significantly. Already, the domestic industry is being forced to reduce the price due

to dumped imports and offers made by the imports from the subject countries.

- v. The producers in the subject countries are understood to be holding significant capacities for the subject goods. Thus, large-scale imports are imminent, should the dumping not be checked at this stage.
- vi. The dumped imports of Flexible Slabstock Polyol are causing injury to the domestic industry who is also facing a threat of further injury from large imports likely to come in near future.

C. IMPORTERS' AND USERS' VIEWS

4. The submission have been made on behalf of M/s Sheela Foam Pvt. Ltd., M/s Feather Foam Pvt. Ltd., M/s Soft Foam Pvt. Ltd., M/s Bharat Foam Udyog Pvt. Ltd., M/s Multivyn Foam Pvt. Ltd., M/s J.J.Foams Pvt. Ltd., M/s MH Polymers Pvt. Ltd., M/s Welbros Foam Pvt. Ltd., M/s Arvind International Limited, M/s Kansaf Foam Pvt. Ltd., M/s Fylfor Comforts Pvt. Ltd., M/s Tirupati Foam Ltd., M/s SSF Industries Ltd and M/s Joy Foam Private Ltd., which are as under:-

- (a) That it is the considered opinion of various technical experts that the viable size of a Polyol Plant is in the region of 80000 MTPA. The standard technology is the Styrene Monomer/Propylene oxide (SMPO Route). Only with this technology and the aforesaid capacity can a Polyol Plant be commercially viable. Any reduction in the capacity or change in technology, would automatically lead to very high costs of production. However, the Petitioner's plant has capacity of only 14000 MTPA and does not employ SMPO Route technology. That the Petitioner's production process and the utilities are technologically obsolete and are not commercially viable and as a consequence the price of the product manufactured by the Petitioner are unrealistically high.
- (b) That due to the inferior technology used by the Petitioner, the quality of Flexible Slabstock Polyol is materially and adversely affected and the same in turn affects the manufacture and quality the downstream products using Flexible Slabstock Polyol as raw material.
- (c) That by its final findings dated 17.09.1998 the Directorate General of Safeguards had imposed safeguard duty in respect of Flexible Slabstock Polyol. That in the present case the domestic industry is deliberately attempting to abuse the machinery of the Hon'ble Designated Authority to derive an undue advantage and unwarranted protection to itself. The domestic industry has failed to make such necessary commercial and operational measures as were required for it to become commercially

viable. That the Petitioner was granted a period of 18 months for positive adjustments. That the domestic industry should not be allowed to take undue advantage of their own inefficiency especially when the alleged injury is entirely due to its own inefficiencies and does not have any relation whatsoever to the import of Flexible Slabstock Polyol.

- (d) That the Petitioner is a multi-product company and manufacture Propylene Oxide, Propylene Glycol, Di Propylene Glycol, Tri Propylene Glycol and DCP and DCIPE apart from various categories of Polyol. In the circumstances, it is extremely difficult to ascertain the fixed costs allocation to the Flexible Slabstock Polyol. The Petitioner must clearly set forth the apportionment of fixed costs and overheads proportionate to and in respect of the manufacturer of Flexible Slabstock Polyol. That the Petitioner has failed to demonstrate the same.
- (e) That the production of Flexible Slabstock Polyol by the Petitioner is not regular and is seasonal i.e. Flexible Slabstock Polyol is not manufactured throughout the year but is manufactured in trenches. In the circumstances, the Petitioner should not be allowed to allocate fixed costs component spread over the whole year while the article is manufactured for a limited period. That the Petitioner has deliberately failed to disclose the said facts and is seeking to take undue advantage by apportioning a higher costs of production in respect of Flexible Slabstock Polyol. That the Hon'ble Designated Authority should direct the petitioner to provide all necessary and detailed data with respect to its cost allocations.
- (f) That the Petitioner is the only manufacturer of the product in India. That the Petitioner has filed the present petition to consolidate its monopoly in India and to avoid any competition from technologically superior and commercially viable imports despite its operational and commercial inefficiencies. The total capacity of the Petitioner is woefully short of the demand of Flexible Slabstock Polyol in India. The demand for Flexible Slabstock Polyol in India is around 35000 MTPA and is currently growing at the rate of 10%-15% p.a.
- (g) That the prices of almost all chemicals and plastics have exhibited a downward trend during the past year including the period under review. However, the Petitioner has deliberately omitted the mention of the same. It is further submitted that the normal value claimed by the Petitioner is high while the international prices are much lower and is evidently highly imaginary and unsupported while also being factually wrong. It is in fact the prices of the product manufactured by the Petitioner that have remained unrealistically high and unviable.

Out of these importers, M/s Sheela Foam Pvt. Ltd. and M/s Joy Foam Pvt. Ltd. have submitted information in the prescribed Importer's Questionnaire.

The information is incomplete as both these firms have not submitted the requisite annexures to the Importer's Questionnaire.

5. M/s Tirupati Foam Ltd. submissions are as under:-

That they have been using a special grade of heteropolyol voranol 3010 from one of the reputed multi-national manufacturers and the said product is imported by them directly. This special grade polyol is presently not manufactured by the domestic producer. That they have sophisticated manufacturing facility which demand special technical requirements which they are not able to get from the domestic manufacturers. The domestic producers has protection of customs duty and special additional duty and any further levy of duty would be detrimental to their business.

The company has submitted some information under the Importers' Questionnaire but have not submitted all requisite annexures as required under the Importer's Questionnaire

6. M/s DP Foam Pvt. Ltd. submissions are as under:-

That the domestic polyol industry seeking protection against anti dumping should be asked to maintain quality at par with international standards and should also be cost effective. The domestic industry is not doing any cost analysis and are fixing their price compared to international price. The quality of their material varies from batch to batch. The domestic industry should maintain quality and have a pricing policy according to their cost of production.

7. M/s U-Foam Pvt.. Ltd submissions are as under:-

That the issue of a local industry being placed at disadvantage due to low prices from imports is not particularly applicable to this Product but practically all goods being imported into the country. It would therefore not be a good idea to give protection to the Petitioner. All small scale industries who are hard pressed for liquidity would continue to patronise the products of the Petitioner even though their cost could be slightly higher in view of the fact that the small enterprise is in a position to order in small lots rather than invest for container loads. It would be wise for both local industry as well as the Petitioner to work out on suitable / mutually beneficial cooperation.

D. EXPORTERS' VIEWS

8. Responses have been received from M/s Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd., Singapore, M/s The Dow Chemical Co. USA, and M/s Bayer Polyurethanes Asia Pte. Ltd., Singapore.

(I) The submissions of M/s Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd., Singapore, are as follows:-

- i. That M/s Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd., Singapore made only marginal sales in Singapore which are minimal compared to the exports and therefore, normal value of the said products can be determined on the basis of the cost of production.
- ii. That the producer in Singapore has several advantages with regard to the cost of production and they share common facilities and logistics with other products.
- iii. That their company exports the majority of the said product in the Asia Pacific and other regions including India and sells only a minimal amount of its total production in the domestic market at Singapore, the cost of production of the said product in Singapore with addition of SA&G overheads and profit be considered as the basis for determining the normal value.
- iv. That the market of the said product in India is greater than the total installed capacity of the Petitioner hence import of the said product is absolutely imperative and necessary.
- v. That the petitioner's case is based on extrapolated information which cannot be considered sufficient to meet the requirements of an anti dumping investigation.
- vi. That the information submitted by the petitioner cannot be considered as accurate as the same has been obtained from secondary sources and are unsubstantiated.
- vii. That the primary impact on the profitability of the petitioner is due to the cost associated with the production plant and the cost of the raw materials. It has further been argued that deterioration in just one or two indices cannot be considered sufficient to substantiate the allegation of material injury.

- viii. The description used in the definition of the product under consideration is too broad.
- ix) There are several methods of producing Polyol Oxide which is the feedstock for the subject goods. Each method has a different set of production and economic dynamics. The process used by the exporter has an advantage over the Chlorohydrin process used by the petitioner as the process adopted by the exporter converts the major raw material i.e., Propylene into the finished product more efficiently and has less waste.

(II) The submissions of M/s Dow Chemical Co., USA are as follows:-

- i) That the applicants M/s MPL are the sole producers of this product in India and the sole reason of their taking over erstwhile Spic Organics Ltd. is to establish monopoly to enable them to dictate terms to the users, all of whom belong to small scale sector.
- ii) The market demand for Flexible Slabstock Polyol is 16200 MTPA and growing @ 10%-12% p.a. The Petitioners have plants of small capacities and also manufactures different grades of Polyols for different applications. The Petitioner being the sole domestic producer does not have the capacity to fulfill the demand and the balance demand needs to be supplemented by imports.
- iii) The Petitioner has an approved / licenced capacity of 37,000 MT of Polyol, however, in order to continue with its monopolistic activity have done nothing constructive to increase their capacity utilisation so as to discourage new entrants in the field.
- iv) That the product of Dow is different from manufactured by the Petitioners. The said product is used in manufacture of Flexible PU Foam. This PU Foam is manufactured by two methods in India viz. Continuous foaming and box foaming. Although the raw material used for both these methods are similar, the continuous foaming method requires high product quality and more importantly consistency in specification from batch to batch.
- v) The Petitioner's claim that its product and the imported product are identical is not the full truth. In Flexible Slabstock Polyol, depending upon the use of Propylene

Oxide (PO) or a combination of the same with Ethylene Oxide functional group (EO), Homo Polymers (Only PO) or Hetero Polymers (combination of EO and PO) are made. It is pertinent to note that majority of the Dow Polyol or FSP being imported from US is Hetero Polyol, whereas the majority of that being produced by MPL is Homo Polyol.

- vi) That the volume of imports have decreased significantly from the subject countries during the last three financial years. That the data collected by the Petitioners is only for seven months which is then extrapolated. The sale of the product being cyclical with the month of April, May and June typically being the slump period, the extrapolated figures are highly inaccurate and cannot be relied upon. Moreover, even accepting Petitioner's extrapolation method, subject imports have decreased both in terms of absolute quantity and in market share. During each period, subject imports have decreased. Secondly, the data submitted by the Petitioner is collected from secondary sources, which may not fit with actual, or data from primary sources.
- vii) That the subject imports from USA have not affected prices adversely. The CFR price for imports for the POI into India is in line with the prices in the neighbouring countries.
- viii) That the Petitioner have proceeded on a totally erroneous basis for arriving at the normal value. The inability of the Petitioner to collect price data of the exporting countries which is available with many agencies makes their exercise of constructing cost of product in the exporting countries an exercise in imagination. The Petitioner's claim of unavailability of price data is absolutely baseless.
- ix) That the PO manufacturing facility of the Petitioner is of a size that does not allow for production of PO at an economically viable cost. It should be noted that world scale plants for PO are typically in excess of 1,50,000 MTPA.
- x) That the Petitioner has been able to realise a healthy price increase of 15% over the last three years despite the product prices remaining relatively flat in the international market.

- x i) That the Petitioner appears to have compared the inventory of pre-merger entity with post-merger entity and the increase in inventory is primarily due to comparison with peak and slump seasons rather than a sign of Injury due to imports.
- x ii) That there is no justification/justifiable evidence that the profitability of the Petitioner has been affected by the import of FSP.
- x iii) That because of their in-house problems, the Petitioner can neither increase its share nor improve its profitability, even in the absence of alleged dumping.

(III) The submissions of M/s Bayer Polyurethane Asia Pte. Ltd., Singapore as follows:

- i) That they are regular suppliers of the said product in India for the last 25 years backed by their most reliable technical support.
- ii) Their products are backed by well known and established technology and have a consistent demand in the Indian market and are well accepted in the slabstock foam market in India.
- iii) That they never had intention to cause injury to the Indian Slabstock Polyol market.
- iv) That the current Indian Flexible Slabstock Polyol Market size is around 16,000 MTs p.a which has been growing at a double figure growth rate of about 11-12% for the past three years. The domestic production capacity is not enough to meet the growth demand, therefore the shortfall has to be met via imports.
- v) That the domestic producer, M/s Manali Petrochemicals Ltd., has been seeking protection continuously. The economic viability of their operations depends on efficient production process and a larger economic production capacity. But unfortunately they have not been able to achieve either in the last three years despite of the fact that a safeguard was imposed to their favour.
- vi) That there is a general global slowdown of the economy and prices of almost all polymers in general are under

pressure. The trend of pricing of Flexible Slabstock Polyol for India has been consistently at par or higher than prices prevailing in the Asia Pacific region and as such cannot be reflected as specific case of dumping into India.

- vii) That the Indian market already has the highest protection duty in the Asia Pacific region i.e. , 35% basic custom duty which actually cascades upto over 42% with the addition of other duties. Whereas, the per capita consumption of Flexible Slabstock Polyol in India is lowest in the region being almost 1/20th in comparison to China and other developing countries. Any further protection will increase costs to the consumer and hamper consumption growth / industrial growth of the segment.
- viii) That the imports into India have also been effected by the escalating exchange rates that have an additional impact of about 5% in the last one-year.
- ix) That Manali Petrochemicals Ltd., and Spic Organics have merged to form one company and have adopted a monopolistic attitude. The respondents presence in the market restricts monopolist practice and protects consumer by encouraging fair pricing

E. EXAMINATION AND FINDINGS BY AUTHORITY

9. The submission made by the importers, exporters, users, domestic industry and other interested parties have been examined and considered while arriving at these findings and wherever appropriate have been dealt hereinafter.

10. The cases of new exporters or those stated to be willing to give price undertaking shall be considered, on request, by the Authority in accordance with the Rules supra.

F. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

11. The product under consideration in these investigations has been considered as "Flexible Slabstock Polyol of Molecular Weight 3000 to 4000". These products are classified under Chapter Heading 3907.20 of the Customs Tariff Act but the same have also been cleared under Chapter Headings 3907.91 and 3907.99. The exporters have claimed that the product description is too broad. However, no substantive arguments have been

advanced to indicate that this description covers any products more than what had been intended by the petitioner and thereafter accepted by the Authority for the scope of investigation. The Authority therefore considers that the description of the product under consideration is precise and accurate. It may be mentioned that the customs classifications are indicative only and are in no way binding on the scope of the present investigation.

12. The petitioners have claimed that the goods produced by them are like articles to the goods originating in or exported from the subject countries. An issue has been raised that the product produced by the petitioners and the imported products cannot be considered as like articles. It has been contended that in Flexible Slabstock Polyol, depending upon the use of Propylene Oxide or a combination of the same with Ethylene Oxide functional group, Homo Polymers or Hetero Polymers are made. They have further argued that it is pertinent to note that majority of the Polyol being imported from US is Hetero Polyol, whereas the majority of that being produced by MPL is Homo Polyol.

The issue has been examined by the Authority. The basic objection of the exporter's is that the Polyol Oxide, which is the main feedstock for the production of the subject goods, is obtained by different methods and, therefore, the resultant Flexible Slabstock Polyol cannot be considered as like articles. It may be mentioned here that the tests of determining whether any two products are like articles or not, inter alia include the determination of whether the two products are technically and commercially substitutable or not. No arguments have been advanced nor has any evidence been forwarded to substantiate their argument that the goods produced by the domestic industry and those imported into India are not like articles. The Authority, therefore, has determined that the goods being imported are like article to the product under consideration.

G. DOMESTIC INDUSTRY

13. The petition has been filed by M/s Manali Petrochemicals Ltd. (MPL), who are the only producers of the subject goods in the country. Therefore, they have the standing to file the application on behalf of the domestic industry. Further, the petitioners have neither imported the subject goods nor are they related to any importer/exporter of the subject product. The petitioners, therefore, satisfy the criteria of standing to file the petition on behalf of the Domestic Industry in terms of Rule 5(3) (a) of the Rules supra.

H. NORMAL VALUE, EXPORT PRICES & DUMPING MARGINS

14. The Authority sent questionnaires to all the known exporters for the purpose of determination of normal value in accordance with Section 9A(1)(c). However, none of the exporters from European Union and Japan responded to the Authority nor have they furnished any information. The Authority, therefore, holds that none of the exporters from European Union and Japan have cooperated with the Authority as envisaged under the Rules and Rule 6(8) is attracted in their case.

15. The Authority observes that the exporter from USA viz. M/s The Dow Chemical Co., who has sent their comments, has not sent its reply in the prescribed proforma of this Directorate. Further, they have not submitted any information which can be made use of in the investigations. The exporter has merely submitted some reports without giving any information with regard to either the normal value, export prices or the cost of production. For the purpose of determination of individual dumping margin, the said exporter is considered as non-cooperative and the Authority shall proceed on the basis of the best information available to it as per Rule 6(8) *supra* for this exporter as well as for other exporters from USA.

16. From Singapore two exporters have responded to the initiation notification viz. M/s Bayer Polyurethanes Asia Pte. Ltd. and M/s Shell Eastern Petrochemicals Pte. Ltd. As regards M/s Bayer, no details regarding export price, domestic sales price, cost of production, adjustments regarding freight, insurance, credit sales, discounts, etc. have been given in the prescribed format. As regards M/s Shell Petrochemicals Pte. Ltd., Singapore who has filed the response, it is observed that the said exporter has failed to provide any non-confidential version of the appendices to the Exporter's Questionnaire. Further, the Exporter has not provided any details of their sales/credit arrangement, installed capacity and production of other goods, the allocation of plant and machinery for the product, incidence of interest with regard to their cost of production/export sales, etc.. There is no indication of any kind of finance charges in the cost of production whereas the balance sheet shows that the Company has incurred expenses on this account. The reconciliation in respect of sales of the product under consideration and other products as required for Appendices 3 and 7 have not been provided. The information in respect of related companies specifically relating to trading/manufacturing companies have not been provided. It is therefore observed that the response submitted by the exporter cannot be considered as a complete response. For the purpose of preliminary findings, therefore the Authority has decided to use the best information available in terms of Rule 6(8) *Supra* in case of all the exporters from Singapore.

17. It has been argued by the exporters/importers that the information supplied by the domestic industry with regard to imports cannot be relied upon as accurate since the same has been obtained from secondary sources. In the absence of availability of data from DGCI&S, the Designated Authority has been consistently relying upon the information made available to it from other sources also. This practice is entirely consistent with the legal position. However, as a part of the detailed investigation, the Authority is making use of the information received from the participating exporters/importers to arrive at the export volumes and values for the determination of dumping margin as well as for injury assessment. Further adjustments has been given on account of freight, marine insurance, commission, port handling etc., to arrive at net export price on the basis of information available.

18. The principles governing the determination of normal value, export price and the dumping margin as laid down in the Custom Tariff Act and the Anti Dumping Rules are elaborated in Annexure I to the Rules. The dumping margins arrived at for the purpose of preliminary findings are as follows:

Country/Territory	Exporters/ Manufacturers	Dumping Margin (%)
USA	All exporters	46.01
Japan	All exporters	42.19
EU	All exporters	38.60
Singapore	All exporters	32.27

I. INJURY

19. Rule 11 of Anti Dumping Rules reads as follows:

"Determination of Injury:

- i. In the case of imports from specified countries, the designated authority shall record a further finding that import of such article into India causes or threatens material injury to any established industry or materially retards the establishment of any industry in India;
- ii. The designated authority shall determine the injury to domestic industry, threat of injury to domestic industry, material retardation to establishment of domestic industry and a causal link between dumped imports and injury, taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on price in the domestic market for like articles and the

consequent effect of such imports on domestic producers of such articles and in accordance with the principles set out in Annexure II to these rules."

20. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree. For the examination of the impact on the domestic industry in India, the Authority considered such further indices having a bearing on the state of industry as production, sales, stock, profitability, net sales realization etc.

Cumulative Assessment of Injury

21. It is observed from the facts available on record that the margins of dumping from each of the subject countries are more than the 2% limit expressed as % of export price. Also the volumes of imports from each of the country are more than de minimis. Cumulative assessment of the effects of imports would be appropriate since the exports from the subject countries directly compete with each other and with the goods offered by the domestic industry in the Indian Market. The Authority, therefore, proposes to assess injury to the domestic industry from the subject countries cumulatively.

Market share of the imports from Subject countries

22. It can be seen from the following table that the market share of the imports from the subject countries as a percent of the total imports has increased from 83.72% in the year 1999-2000 to 91.73% during the period of investigation. Since all the importers or exporters have not provided the information in the prescribed format, it is quite likely that the actual quantum of imports may be much higher if the imports from the ICDs particularly at Delhi and bulk shipments at Kandla are taken into account, the information on which is yet to come and shall be taken into account in the final findings.

Market Share of Imports from Subject Countries (% of Total Imports)

Year	Imports from the subject countries (MT)	Total Imports	% share
1998-99	2350.12	2383.72	98.59%
1999-2000	1983.15	2368.65	83.72%
Oct 2000-June 2001	1631.97	1779.07	91.73%

Market Share of Imports from Subject Countries (% of Total Demand)

23. As would be revealed from the following table, the market share of imports from the subject countries as a proportion of total demand has also sharply risen from 19.43% during 1999-2000 to 22.08% during the period of investigation.

Year	Imports (MT)	Total Demand	% share
1998-1999	2350.12	8900.58	26.40%
1999-2000	1983.15	10207.21	19.43%
Oct 2000-June 2001	1631.97	7390.16	22.08%

Production & Capacity Utilization

24. It has been observed that despite the marginal increase in the production and the capacity utilization of the domestic industry during the period of investigation, the domestic industry has incurred losses due to poor price realization. It is therefore clear that the domestic industry could retain its customers and market share at the cost of suffering on the financial parameters. Thus, the apparent increase in production as well as capacity utilization has to be seen in the context of the price effect of the dumped imports.

Year	Capacity (MT)	Production (MT)	Capacity Utilization (%)
1998-1999	***	***	***
1999-2000	***	***	***
Oct. 2000-June 2001	***	***	***

Sales Volume & Value of the Domestic Industry

25. As regards the sales price, there is some marginal improvement over the last year but it has been claimed by the domestic industry that the increase in price is due to fall of Rs. as compared to the \$ and the increase in the cost of the major raw materials and fuel. This is also reflected in the fact that the losses have gone up despite marginal increase in the sales prices. At the same time, it is the claim of the domestic industry that it is not feasible for the domestic industry to increase their prices despite increase in the raw material prices precisely because of dumping. Thus, there is enough evidence of price suppression on account of dumping by the subject countries.

Year	Sales Volume (MT)	Sales Value (Rs. In lakhs)	Unit Price (Rs./MT)
1998-1999	***	***	***
1999-2000	***	***	***
Oct. 2000-June 2001	***	***	***

Profitability

26. An examination of the records of the domestic industry indicates that the domestic industry has suffered serious injury in the form of direct losses per unit of sale. Thus, it is apparent that it is the price factor alone which can be considered to have led to injury to the domestic industry resulting in losses despite improvement in capacity utilization as well as production.

Year	Sales Value (Rs. In lakhs)	Cost of Sales (in lakhs)	Profit/Unit
1998-1999	***	***	***
1999-2000	***	***	***
Oct 2000-June 2001	***	***	***

Price Undercutting

27. It has been claimed that dumping by the subject countries has had a significant impact on the net sales realization by the domestic industry for the subject goods. To hold on to its market share, the petitioners had to compete with low priced and dumped imports of subject goods from the subject countries. The landed values of the dumped imports also indicate that there is price under-cutting taking place.

Price Underselling

28. The Authority has also examined the claim of the domestic industry that the domestic industry is suffering on account of direct losses. The Authority notes that price underselling is an important indicator to make an assessment of injury. The Authority has worked out a fair selling price and compared the same to the landed value to arrive at the extent of price underselling.

Employment

29. The employment figures also show the effect of injury as there is a drop in the employment level despite the fact that it is usually not feasible to reduce manpower due to the existing labour laws.

7844 9/2/01-6

Increase in Inventories

30. The domestic industry has claimed that it was not able to sell its products in the market due to massive dumping. This is also revealed from the fact that the inventory in one of the two plants had increased from *** as on *** MT as on 31.3.2000 to *** MT at the end of June 2001, an increase of over three times. Further, they have been already forced to cut down their production due to the huge pile up of inventories. The inventories in the second plant are also at a very high level of *** MT. The overall increase in inventories taking both plants together show an increase of 61% during POI as compared to year 1999-2000.

31. On examination of the evidence, it has been found that there is marginal increase in production, sales, and capacity utilization of the domestic industry. However, the domestic industry is suffering losses on account of low priced and dumped imports from the subject countries. The most significant parameter evidencing injury is the price undercutting and price underselling as per the evidence available with the Authority.

The volume of imports in relative as well as absolute terms has gone up. Market share in the total demand also shows an increase. The above factors clearly show the injury being suffered by the domestic industry. On the basis of the evidence available before the Authority, it is determined that the domestic industry has suffered injury and is suffering further threat of injury during the period of investigation.

J. CAUSAL LINK

32. In determining whether material injury to the domestic industry was caused by the dumped imports, the Authority took into account the following facts:-

a. Substantial imports of subject goods from Subject countries at dumped prices has resulted in losses to the domestic industry.

b. The authority also observes that there is a single market for the subject goods where dumped imports compete directly with the goods produced by the domestic industry. Demand for subject Flexible Polyol is showing a healthy growth. Decline in demand is hence not a factor causing injury to the domestic injury. The imported product is sold to meet the similar commercial grades and standard specifications, as domestically produced Flexible Polyol. The imported subject article and the domestically produced goods are like articles and are used for the same applications/end uses. Thus, pricing becomes the most important factor determining purchase of the article from either imported sources or domestic sources.

c. The imports from Subject countries suppressed the prices of the product in the Indian market to such an extent that the domestic industry was prevented from recovering its full cost of production and earn a reasonable profit from the sale of subject goods in India.

K. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST

33. The purpose of anti dumping duties is to eliminate dumping which is causing injury to the domestic industry and to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market which is in the general interest of the country.

34. The Authority recognizes that the imposition of anti dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products. However, fair competition on the Indian market will not be reduced by the anti dumping measures. On the contrary, imposition of anti dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. The Authority notes that the imposition of anti dumping measures would not restrict imports from Subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The consumers could still maintain two or even more sources of supply.

L. OTHER ISSUES

35. It has been claimed by the importers, exporters and some interested parties that the petitioner, i.e., MPL, is the only producer of the subject goods in the country, and therefore, the present petition has been filed by them to consolidate their position as a monopoly producer in India and to avoid any competition. Further, the total capacity of the petitioner is woefully short of the demand of FSP in the country and the size of the plants is uneconomical. It has also been argued that the technology used by the domestic industry is obsolete and inferior. Issues have also been raised regarding the poor quality of the goods produced by the domestic industry as well as the methodology adopted for apportionment of fixed costs and overheads to the production of FSP. It has also been stated that the international prices of almost all chemicals and plastics including FSP have exhibited downward trend during the last couple of years and that the prices of exports to India are at the prices prevailing in international market. It has also been brought out in the submissions by the importers and the users that safeguard duty was imposed on the subject goods vide Final Findings dated 17.9.1998 and that the domestic industry is deliberately attempting to abuse the machinery of the Designated Authority to derive an undue advantage.

36. The above issues have been examined by the Authority. The purpose of anti dumping duty is to ensure that any injury caused to the domestic industry due to dumping is addressed adequately. The fact that there is a single producer of the subject goods in the country does not, in any way, restrict the right of the domestic producers to claim relief from the Designated Authority against the dumped imports under the Anti Dumping Rules. It has been the accepted position that anti dumping duty is in the nature and form of providing a remedy against the trade distorting practice of dumping. Further, anti dumping duties do not propose to restrict or block imports from any sources and therefore, the issue of the domestic supply being short of the total consumption in the country, has no relevance. Also since alternative sources of supply are available to the Indian industrial users, the apprehension of the petitioner company exercising monopoly position to exploit the customers, is misplaced. Adequate care has been taken by the Authority while apportioning the fixed cost and other overheads to the product under consideration. As regards the issue of safeguard duty having been imposed on the subject goods in the past, the Authority is of the view that there is no bar on the domestic industry to seek protection against dumped imports only because the said goods had safeguard duties in the past. Regarding the issue of the export prices to India being at par with the prevailing international prices, the Authority notes that dumping is linked to the normal value in the exporting country and export prices of the subject goods to India and while determining the normal value, it has to be established that the sales are in the ordinary course of trade.

M. CONCLUSIONS

37. The Authority has, after considering the foregoing, come to the conclusion that:

- (i) Flexible Slabstock Polyol as defined above in the para relating to Product under consideration has been exported to India from Subject countries below its normal value;
- (ii) the Indian industry has suffered material injury;
- (iii) the injury has been caused by the dumped imports from subject countries;

38. The Authority considers it necessary to impose an anti dumping duty provisionally, pending final determination, on all imports of Flexible Slabstock Polyol from subject countries in order to remove the injury to the domestic industry. The margin of dumping determined by the Authority is indicated in the paragraphs above. The Authority proposes to recommend the amount of anti dumping duty equal to the margin of dumping or less, which if levied, would remove the injury to the domestic industry. For the purpose of determining injury, the landed value of imports is proposed to be compared

with the non-injurious selling price of the petitioner companies determined for the period of investigation.

39. Accordingly, the Authority recommends that the provisional anti dumping duties be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government on all imports of Product under consideration originating in or exported from subject countries pending final determination. The anti-dumping duty shall be the difference between the prices indicated in Column 3 of the following table and the landed value of the concerned imports:

Country/Territory	Exporters/ Manufacturers	Amount US D per MT
1	2	3
USA	All exporters	1804
Japan	All exporters	1804
EU	All exporters	1804
Singapore	All exporters	1804

40. Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

N. FURTHER PROCEDURE

41. The following procedure would be followed subsequent to notifying the preliminary findings:

- a. The Authority invites comments on these findings from all interested parties and the same would be considered in the final findings;
- b. Exporters, importers, petitioner and other interested parties known to be concerned are being addressed separately by the Authority, who may make known their views, within forty days from the date of preliminary findings. Any other interested party may also make known its views within forty days from the date of publication of these findings;

- c. The Authority would provide opportunity to all the interested parties for making oral submissions which have to be rendered thereafter in writing;
- d. The Authority would conduct further verification to the extent deemed necessary;
- e. The Authority would disclose essential facts before announcing final findings.

L.V. SAPTHARISHI, Designated Authority